

महिलाओं की आय बढ़ाने वाली गतिविधियों को मिले बेहतर बाजार : सीईओ

स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद कर उत्पादन, बिक्री और आय की ली जानकारी, योजनाओं की समीक्षा कर समय-सीमा में कार्य पूरा कराने के निर्देश

सिंगरौली। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संघप्रिय ने बुधवार को जनपद पंचायत चितरंगी का भ्रमण कर मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों का मैदानी निरीक्षण किया। उन्होंने स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद कर उनकी आय, रोजगार, उत्पादन और बाजार से जुड़ाव की जानकारी ली। भ्रमण की शुरुआत ग्राम समुआर से हुई। यहां अहिल्याबाई स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित हैंडलूम गतिविधि



का निरीक्षण करते हुए सीईओ ने उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता, बिक्री और मार्केट लिंकेज की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उत्पादों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद 'एक बगिया मां के नाम' अभियान के तहत पोधरोपण कार्य का निरीक्षण कर पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल पर जोर दिया। ग्राम कतरीहार में पुलेट-ब्रीडर फीड

बिक्री और आय की जानकारी ली। गतिविधि का विस्तार कर इसे नियमित एवं लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। मैदानी निरीक्षण के बाद जनपद पंचायत चितरंगी में समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास, आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ ने अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने, पंचायत भवनों की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और पात्र हितग्राहियों के आवास शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आजीविका मिशन की समीक्षा में स्व-सहायता समूहों के बैंक लिंकेज, महिलाओं की आय वृद्धि और आजीविका गतिविधियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का त्वरित एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।

पंचायतों में 31.50 लाख की वित्तीय अनियमितता, दोषियों पर शिकंजा

खुटार में 20.82 लाख की गड़बड़ी पर सरपंच-सचिव को वसूली नोटिस, खटाई में बिना काम कराए 10.67 लाख रुपये निकालने का मामला

सिंगरौली। ग्राम पंचायतों में शासकीय राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ प्रिय ने सख्त रुख अपनाया है। जांच में दो ग्राम पंचायतों में कुल 31 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की अनियमितता सामने आने के बाद संबंधित जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के विरुद्ध वसूली एवं दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्राम पंचायत खुटार निवासी लक्ष्मी नारायण की शिकायत पर गठित संयुक्त जांच दल ने 11 जून 2026 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें विभिन्न निर्माण कार्यों में 20 लाख 82 हजार



368 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई। मामले में आठ सितंबर को वर्तमान सरपंच श्रीमती सरिता पनिका के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही धारा 92 के तहत 10 लाख 41 हजार 184 रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया। तत्कालीन सचिव अशोक कुमार शाह के विरुद्ध भी इतनी ही राशि की वसूली के लिए

कार्रवाई की गई है। इसी तरह ग्राम पंचायत खटाई में शिकायत की जांच के दौरान 10 लाख 67 हजार 700 रुपये बिना निर्माण कार्य कराए शासकीय राशि के आहरण का मामला सामने आया। कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर पूर्व सरपंच छोटेलाल कोल, क्षेत्रीय पीसीओ रमई कोल और सचिव भगवान सिंह के विरुद्ध धारा 89 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सीईओ संघ प्रिय ने कहा कि पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय राशि के दुरुपयोग में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध वसूली के साथ दंडात्मक और वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

पंचायतों को बाल हितैषी बनाने की पहल, सरपंच-सचिवों को दिया प्रशिक्षण

सिंगरौली। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत बैदन सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में पीरामल फाउंडेशन एवं कैवलया एजुकेशन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 'नींव' कार्यक्रम अंगरंग संपन्न हो, सचिवों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायतों



को बाल हितैषी बनाने तथा उपलब्ध संसाधनों एवं शासकीय योजनाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा,

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने, बच्चों के नियमित स्वास्थ्य एवं पोषण की निगरानी, आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाने तथा अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही

पंचायत मैनेजमेंट यूनिट के गठन की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके माध्यम से प्रत्येक माह पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित कर बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास एवं टीकाकरण की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायत, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग, अभिभावकों तथा समुदाय का समन्वित प्रयास आवश्यक है।

नो-एंट्री में घुसे तीन भारी वाहन, 25,500 रुपये का चालान

बंधौरा पावर प्लांट-बरगवां मार्ग पर यातायात पुलिस की कार्रवाई, निर्धारित समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती



व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाए रखने के लिए लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार 8 सितंबर को शाम करीब 5:30 बजे यातायात प्रभारी सूबेदार आशीष तिवारी के नेतृत्व में टीम ने बंधौरा पावर प्लांट से बरगवां गडेरिया कॉनवाय प्वाइंट मार्ग पर वाहनों की जांच की। चेकिंग के दौरान तीन भारी मालवाहक वाहन निर्धारित नो-एंट्री अवधि में प्रतिबंधित मार्ग पर चलते मिले। पुलिस ने वाहनों को रोककर

दस्तावेज और यातायात नियमों की जांच की तथा नियमानुसार चालानी कार्रवाई की। तीनों वाहनों पर कुल 25,500 रुपये का चालान किया गया। बताया गया कि बंधौरा पावर प्लांट से बरगवां गडेरिया कॉनवाय प्वाइंट तक बंधौरा-रजमिलान-खुटार-परसौना मार्ग पर भारी वाहनों के लिए सुबह 7 से 10 बजे और शाम 5 से रात 9 बजे तक नो-एंट्री लागू है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टर्स से नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक विनय सिंह, पुष्पेंद्र चव्हेदी और आरक्षक जितेंद्र परमार की भूमिका रही।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 11 सितंबर को गनई के गजरहिया में शिविर

सिंगरौली। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं मौके पर निराकरण के लिए 11 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत गनई के ग्राम गजरहिया में धान खरीदी केंद्र के पास जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शिविर स्थल में परिवर्तन किया गया है। पूर्व निर्धारित पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गनई के स्थान पर अब शिविर गजरहिया में धान खरीदी केंद्र के पास आयोजित होगा। शिविर में गनई सहित आसपास के ग्रामों के ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं एवं शासकीय सेवाओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर गौरव बैनल ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

धनहरा में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की कार्यवाही, चार ट्रैक्टर जब्त

सिंगरौली। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश और खनिज अधिकारी आकांशा पटेल के मार्गदर्शन में विभागीय टीम लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसी क्रम में बुधवार को धनहरा क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त चार ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। सहायक खनि अधिकारी रामसुशील चौरसिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान बिना नंबर के चार ट्रैक्टरों को अवैध रेत उत्खनन में संलग्न पाया गया। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को जब्त कर लिया। जब्त वाहनों में सोनालिका डीआई-35, 3032, 434 तथा स्वराज 735 ट्रैक्टर शामिल हैं। कार्रवाई के बाद सभी जब्त वाहनों को पुलिस थाना माड़ा में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जब्त किए गए वाहनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा मामले में आवश्यक दस्तावेज और अन्य तथ्यों की जांच भी की जा रही है।

काचन नदी में उतरे ग्रामीण, पुल निर्माण की मांग को लेकर जल सत्याग्रह

वर्ष 2022 में प्रस्तावित पुल का अब तक नहीं हुआ निर्माण, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने शुरु किया आंदोलन



सिंगरौली। जनपद पंचायत बैदुन की ग्राम पंचायत डिग्धी के राजस्व गांव माटीडांड में काचन नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर बुधवार से आम आदमी पार्टी के बैनर तले जल सत्याग्रह शुरू हो गया। पार्टी जिलाध्यक्ष एवं देवसर विधानसभा क्षेत्र-81 के पूर्व प्रत्याशी रतिभान प्रसाद की अगुवाई में शुरू हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने नदी में उतरकर प्रशासन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारियों का कहना है कि काचन नदी के माटीडांड में वर्ष 2022 में पुल निर्माण प्रस्तावित

किया गया था, लेकिन चार वर्ष बीतने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। पुल नहीं होने से माटीडांड सहित सेमरिया, तेलियाखाड़ी और भदियां क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने पर समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों के अनुसार पुल निर्माण को लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत और मांग की गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। जल सत्याग्रह के दौरान ग्रामीणों ने

जल्द पुल निर्माण शुरू कराने की मांग की। आंदोलन में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष इंदु विश्वकर्मा, यूथ विंग जिलाध्यक्ष अक्षय शाह, ग्रामीण उपाध्यक्ष रावेंद्र शाह, शहर जिला उपाध्यक्ष नीरज कुशवाहा, ग्रामीण कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष चितरंगी संदीप कुमार प्रजापति, ग्रामीण यूथ जिलाध्यक्ष सुजय कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डिग्धी सरपंच मुन्नी देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा।

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान, सात प्रकरण दर्ज

सरई व लंघाडोल क्षेत्र में दुकानों और मकानों पर दबिश, 205 किलो महुआ लाहन समेत 16.13 बीएल शराब जब्त

सिंगरौली जिले में अवैध शराब के संग्रहण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने बुधवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी प्रणय कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सरई वृत्त क्षेत्र के विभिन्न गांवों में की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में देशी-विदेशी शराब और महुआ लाहन बरामद किया गया। कार्रवाई के बाद आबकारी अधिनियम के तहत सात प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आबकारी विभाग के अनुसार सरई थाना क्षेत्र



के ग्राम खानुआखास, गजराबहरा और गोरा में अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान बाबू नंदन सिंह पिता रामलाल सिंह, केशमती सिंह पति पति, रामकरण सिंह, सुष्मिता सिंह पति शंकर सिंह, सियाराम जायसवाल पिता लक्षन धारी सिंह, शांति देवी जायसवाल पति लाला जायसवाल और जगदीश गुप्ता पिता हरिदास गुप्ता के दुकान एवं रियायशी मकान से अवैध शराब तथा महुआ लाहन बरामद किया गया। इसी क्रम में लंघाडोल थाना क्षेत्र के ग्राम पोंडीपाट में प्रेमवती साहू पति राजेश कुमार साहू के ठिकाने पर भी कार्रवाई की गई। विभाग ने संयुक्त रूप से 3.6 बल्क लीटर

देशी मदिरा, 12.53 बल्क लीटर विदेशी मदिरा और 205 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य करीब 27,406 रुपये बताया गया है। आबकारी विभाग ने सभी सात आरोपितों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधन 2000) की धारा 34(1)(क) एवं (च) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक नीलिमा मार्कों, मुख्य आरक्षक बहादुर सिंह तथा आरक्षक धीरू सिंह और अनुज भुजिया मौजूद रहे। विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है।

कोतवाली बैदुन के नए थाना प्रभारी ने संभाला पदभार

सिंगरौली। कोतवाली बैदुन के नवागत थाना प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु द्विवेदी ने बुधवार को थाना पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर थाना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और लंबित मामलों की जानकारी ली। नवागत थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। अपराध नियंत्रण के साथ ही परियादियों की समस्याओं का

त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाएगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि आमजन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। थाना प्रभारी ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों,



नशे के कारोबार, जुआ-सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की बात कही। साथ ही रात्रि गश्त और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने नवागत थाना प्रभारी का स्वागत किया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और आमजन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने का आह्वान किया।

अंधेरे में सुखरा नाला से रोज निकल रहे रेत से लदे ट्रैक्टर

पिपराझांपी में रात के समय कथित अवैध खनन और परिवहन का खेल, रैकी के बाद तय रास्तों से निकलते हैं वाहन

सिंगरौली। कोतवाली बैदुन थाना क्षेत्र की खुटार पुलिस चौकी अंतर्गत सुखरा नाला पिपराझांपी में रात के अंधेरे में कथित तौर पर अवैध रेत का कारोबार धड़झले से चलने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यहां से प्रतिदिन करीब चार से पांच ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन किए जाने का आरोप है। बारिश के मौसम में नदी-नालों से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन की निगरानी के बावजूद गतिविधियां जारी रहने से जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेत से लदे ट्रैक्टर रात के समय नाले के आसपास पहुंचते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर रेत भरने के बाद निर्धारित रास्तों से खाना होते हैं।



सूत्रों का दावा है कि वाहन निकलने से पहले रास्तों की कथित तौर पर रैकी की जाती है। यदि किसी स्थान पर पुलिस अथवा प्रशासन की टीम की मौजूदगी की सूचना मिलती है तो वाहन चालकों को इसकी जानकारी पहुंचा दी जाती है। इसके बाद रास्ता साफ होने पर ट्रैक्टरों को आगे बढ़ाया जाता है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि अवैध रेत परिवहन के लिए प्रति ट्रैक्टर कथित रूप से एक फिक्स रकम निर्धारित है।

हालांकि इस रकम को कौन वसूल करता है और इसका भुगतान किन लोगों तक पहुंचता है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, सूत्र खुटार पुलिस चौकी से जुड़े कुछ कथित कारखानों की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि उनकी कथित सहमति अथवा संरक्षण में रेत परिवहन का खेल संचालित हो रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि प्रतिदिन कई ट्रैक्टर रेत लेकर क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो जिम्मेदार अमला इन वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या रात में निगरानी व्यवस्था कमजोर है या फिर कार्रवाई से पहले ही सूचना लीक हो जाती है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ

सकेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन और खनिज विभाग से सुखरा नाला पिपराझांपी क्षेत्र में रात के समय विशेष निगरानी अभियान चलाने, रेत के स्रोत की जांच करने और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई से ही अवैध रेत कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

इनका कहना है

मैं आज ही ज्वानि किया हूँ, आपके द्वारा जानकारी मिली है, ऐसे अवैध कारोबारी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अमन वर्मा - चौकी प्रभारी - खुटार



आस्था के साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प, घर-घर विराजेंगे माटी गणेश

‘माटी गणेश-सिद्ध गणेश’ अभियान को लेकर कलेक्टर ने दिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

शासी निकाय सदस्य कृष्णकांत द्विवेदी ने जिलेवासियों से मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित करने का किया आह्वान

सीधी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार गणेश उत्सव को पर्यावरण संरक्षण और सनातन परंपराओं से जोड़ने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ‘माटी गणेशदुसिद्ध गणेश’ अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जिले में अधिक से अधिक लोगों को मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि आस्था के साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश घर-घर तक पहुंचे।

अभियान की तैयारियों और जिले में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर बुधवार को कलेक्टर विकास मिश्रा के



साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के शासी निकाय सदस्य कृष्णकांत द्विवेदी तथा जिला समन्वयक मुकेश गौर उपस्थित रहे। बैठक में अभियान की गतिविधियों, जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर विकास मिश्रा ने ‘माटी गणेशदुसिद्ध गणेश’ अभियान को जनअभियान का स्वरूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव समाज के

प्रत्येक वर्ग को जोड़ने वाला पर्व है। ऐसे में यदि धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी घर-घर तक पहुंचे, तो यह अभियान व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। उन्होंने जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान का प्रभावी प्रचार-प्रसार करने तथा विभिन्न माध्यमों से लोगों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए।

शासी निकाय सदस्य कृष्णकांत द्विवेदी ने कहा कि ‘माटी गणेशदुसिद्ध गणेश’ केवल

प्रतिमा परिवर्तन का अभियान नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं को प्रकृति के साथ जोड़ने का संकल्प है। हमारी संस्कृति में मिट्टी और जल का विशेष महत्व रहा है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की स्थापना करके हम अपनी धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं।

उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि इस गणेश उत्सव में अपने घर, संस्थान और सार्वजनिक स्थलों पर मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करें और पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप दें।

जिला समन्वयक मुकेश गौर ने बताया कि जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं, प्रस्फुटन समितियों, नवांकु संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से अभियान को जिले के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। लोगों को पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करने

के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं के महत्व की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान का संदेश घर-घर गणेश, हर घर गणेश, विराजे माटी गणेश है। साथ ही माटी गणेश अपनाएं, प्रकृति का मान बढ़ाएं के संदेश के साथ जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

अभियान के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि गणेश चतुर्थी पर पवित्र नदियों के जल एवं अपने खेत-घर-आंगन की पवित्र मिट्टी से निर्मित माटी गणेशदुसिद्ध गणेश की स्थापना करें। इससे गणेश उत्सव में स्थानीय प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जुड़ाव का भाव मजबूत होगा।

जन अभियान परिषद ने जिलेवासियों से आह्वान किया है कि इस गणेश उत्सव में मिट्टी के गणेश अपनाएं, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित प्रकृति का संदेश दें।

स्व-सहायता समूह ने बदली अनूपा की जिंदगी, खेती से बढ़ी आय और बनीं लखपति दीदी

सीधी। विकासखण्ड रामपुर नैकिन के ग्राम चोरगड्डी निवासी अनूपा कुशवाहा ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपनी मेहनत और बेहतर कृषि तकनीक के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। कभी कृषि कार्य से मात्र 75 हजार रुपये वार्षिक आय अर्जित करने वाली अनूपा आज 2.80 लाख रुपये वार्षिक आय अर्जित कर लखपति दीदी बन चुकी हैं।

अनूपा वर्ष 2010 में संतोषी स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने बचत और ऋण की सुविधा का लाभ उठाते हुए



अपनी कृषि गतिविधियों को विस्तार देने का निर्णय लिया। समूह के माध्यम से 5-6 बार में कुल 7.50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त कर उन्होंने अपने खेत में ड्रिप एरिगेशन की सुविधा स्थापित की।

ड्रिप सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद अनूपा ने अपने खेत में सब्जी की खेती शुरू की। सिंचाई

की बेहतर व्यवस्था, उत्पादन के लिए आवश्यक सुविधाओं और बाजार की उपलब्धता ने उनकी कृषि गतिविधियों को नई दिशा दी। परिणामस्वरूप सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई और उनकी आमदनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई।

आज अनूपा कुशवाहा की वार्षिक आय बढ़कर 2.80 लाख रुपये हो गई है। स्व-सहायता समूह से मिले सहयोग, ऋण सुविधा और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि लखपति दीदी बनकर अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

तेंदुए की खाल की तस्करी में 3 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

डीआरआई की कार्रवाई के बाद वन विभाग ने की विस्तृत जांच, शिकार में प्रयुक्त औजार भी जब्त

सीधी। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) इकाई भोपाल की टीम द्वारा सीधी शहर में तेंदुए की एक खाल के साथ दो व्यक्तियों को पकड़े जाने के बाद वन विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से शिकार में प्रयुक्त किए जाने वाले औजार भी जब्त किए गए हैं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वन मंडल अधिकारी वन

मंडल सीधी प्रीति अहिरवार ने बताया कि 5 सितम्बर को डीआरआई भोपाल की टीम ने थार वाहन में तेंदुए की खाल के साथ दो व्यक्तियों को सीधी शहर में पकड़ा था। वन्यजीव से संबंधित मामला होने के कारण प्रकरण को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग, सामान्य वन मंडल सीधी के परिक्षेत्र सीधी को सौंपा गया।

पूछताछ में आरोपियों अभिषेक सिंह चंदेल उर्फ प्रिंस सिंह पिता पुष्पराज सिंह चंदेल, उम्र 26 वर्ष, निवासी सिहावल, थाना अमिलिया, जिला सीधी तथा

अनमोल सिंह चंदेल पिता रण बहादुर सिंह चंदेल, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बीरदेही, तहसील हनुमना, जिला मऊगंज द्वारा तेंदुए की खाल की तस्करी में शामिल होने की जानकारी दी गई।

आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वन विभाग की टीम ने रीवा वन मंडल के वन परिक्षेत्र हनुमना क्षेत्र के ग्राम धनुहीनार, पोस्ट बीरदेही में दबिश देकर ललन सिंह गोंड पिता चरकू सिंह गोंड, उम्र 53 वर्ष को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से शिकार में उपयोग किए जाने वाले औजार

जब्त किए गए।

वन विभाग द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2022 की विभिन्न धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 25012/18, दिनांक 05 सितम्बर 2026 पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को 6 सितम्बर को जिला न्यायालय सीधी में पेश किया गया, जहां से दो दिन के पर्सनल रिमांड पर लेकर प्रकरण के संबंध में पूछताछ की गई।

7 सितम्बर को आरोपियों को

साथ लेकर घटना स्थल की शिनाख्त कराई गई तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में अन्य आरोपियों के शामिल होने की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी तलाश और पतासाजी की जा रही है।

8 सितम्बर को तीनों गिरफ्तार आरोपियों को पुनः जिला न्यायालय सीधी के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 10 सितंबर को

सीधी। अपर कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन (पूर्वांश) 2026 के लिए मतदान 29 सितंबर 2026 को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक करायी जाएगा। सरपंच एवं जनपद सदस्य पद के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा।

मतदान एवं मतगणना कार्य में लगे कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने

के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। नियुक्त मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 10 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय संजय गांधी स्मृति पी.जी. कॉलेज, नया भवन, सीधी के कक्ष क्रमांक 134 में राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया जाएगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी मास्टर ट्रेनरों को 11 सितंबर 2026

को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय संजय गांधी स्मृति पी.जी. कॉलेज, नया भवन, सीधी में उपस्थित होकर मतदान कर्मियों पीओ एवं पीओ-1 का प्रथम प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार शासकीय संजय गांधी स्मृति पी.जी. कॉलेज सीधी के कक्ष क्रमांक 134 में डॉ. ईश्वर प्रसाद प्रजापति, प्राध्यापक एवं डॉ. दिलीप सोनी,

सहायक प्राध्यापक की ड्यूटी लगाई गई है। कक्ष क्रमांक 126 में विनोद कुमार साकेत, सहायक प्राध्यापक एवं डॉ. मुकेश यादव, सहायक प्राध्यापक तथा कक्ष क्रमांक 221 में राकेश कुमार प्रजापति, सहायक प्राध्यापक को मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार डाइट सीधी के कक्ष क्रमांक 221 में अरुण कुमार मिश्रा, हाई स्कूल प्राचार्य की ड्यूटी लगाई गई है। गिरजा प्रसाद

तिवारी, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल घरभरा तथा रोहिणी प्रसाद पाठक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 सीधी को रिजर्व मास्टर ट्रेनर के रूप में रखा गया है। अपर कलेक्टर ने नियुक्त सभी मास्टर ट्रेनरों को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा तत्पश्चात मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल 10 एवं 11 सितम्बर को सीधी जिले के प्रवास पर

सीधी। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल 10 एवं 11 सितम्बर को सीधी जिले के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री 10 सितम्बर को रात्रि 7 बजे परसिली रिसोर्ट सीधी पहुंचेंगे तथा रात्रि विश्राम

करेंगे।

11 सितम्बर को प्रातः 10 बजे परसिली से सिहावल के लिए रवाना होंगे और प्रातः 11.30 बजे सिहावल पहुंचेंगे। यहां वे शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही युवा संवाद, मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान

कार्यक्रम, हितलाभ वितरण तथा शासकीय जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास सिहावल के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रभारी मंत्री दोपहर 2.30 बजे सिहावल से सर्किट हाउस सीधी के लिए प्रस्थान करेंगे तथा 3 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य से भेंट एवं चर्चा करेंगे।

पीएम स्वनिधि योजना से पथ विक्रेताओं को मिल रहा आर्थिक संबल, लोक कल्याण मेले में ऋण वितरण की कार्यवाही

सीधी। पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें शासन की योजनाओं का सहज जाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद सीधी में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत लोक कल्याण मेले का आयोजन 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2026 तक किया जा रहा है। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी महमूद हसन के मार्गदर्शन में आयोजित इस मेले के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। लोक कल्याण मेले में पीएम स्वनिधि योजना के पात्र हितग्राहियों के ऋण आवेदन, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के आवेदन तथा हितग्राही प्रोफाइलिंग का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हितग्राहियों को योजना की पात्रता, ऋण प्राप्त करने

नगर पालिका सीधी में 30 सितम्बर तक आयोजित हो रहा लोक कल्याण मेला

की प्रक्रिया, डिजिटल लेन-देन और योजना से मिलने वाले विभिन्न लाभों की जानकारी भी दी जा रही है। अभियान के क्रम में 08 सितम्बर 2026 को लगभग 30 हितग्राहियों के ऋण आवेदन करार ऋण वितरण की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड तथा योजना के अंतर्गत उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई।

नगर पालिका द्वारा मेले के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पात्र पथ विक्रेताओं को ऋण एवं अन्य सुविधाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल

सके। योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को अपनी छोटी व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

लोक कल्याण मेले के दौरान हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद का उद्देश्य है कि अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा जाए और उनकी आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाया जाए। नगर पालिका परिषद सीधी ने सभी पात्र पथ विक्रेताओं एवं हितग्राहियों से अपील की है कि वे लोक कल्याण मेले में उपस्थित होकर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य पात्र सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें।

नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन रवाना

जिला न्यायालय सीधी सहित चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में 12 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय सीधी सहित सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने तथा आमजन को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने के उद्देश्य से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं



सत्र न्यायाधीश प्रयागलाल दिनकर ने जिला न्यायालय परिसर सीधी से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रचार वाहनों के माध्यम से जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पम्पलेट एवं फ्लैक्स बैनरों के जरिए नेशनल लोक अदालत तथा विद्युत प्रकरणों में उपलब्ध विशेष छूट की जानकारी आमजन

तक पहुंचाई जाएगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयागलाल दिनकर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक एवं सिविल प्रकरण, विद्युत अधिनियम, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, भ्रण-पोषण के लॉबि प्रकरण तथा नगर पालिका, विद्युत विभाग

एवं दूरसंचार से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते एवं सुलह के आधार पर नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का त्वरित, सरल एवं प्रभावी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आमजन एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं। इस अवसर पर यतीन्द्र कुमार गुरु विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत, दीपक शर्मा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मनीष कुमार श्रीवास्तव द्वितीय जिला न्यायाधीश, सतीशमणी

शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस सीधी में शिक्षकों का गरिमामय सम्मान

सीधी। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, सीधी में शिक्षक सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए शिक्षकगणों का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. प्रभाकर सिंह के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर डॉ. के. एस. नेताम, डॉ. अनिल सिंह, डॉ. संदीप देव पाण्डेय, डॉ. के. बी. सिंह, डॉ. अरविंद त्रिपाठी, डॉ. आई. पी. प्रजापति, डॉ. पुष्पेंद्र शाह, डॉ. गुलाम सहित महाविद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. दिलीप सोनी ने किया। डॉ. अनिल सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आदर्श शिक्षक केवल विषय का ज्ञान देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने आचरण, अनुशासन, संवेदनशीलता और समर्पण के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन की सही दिशा प्रदान करता है। उन्होंने शिक्षक के श्रेष्ठ गुणों को अपने व्यवहार और जीवन में



आत्मसात करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। उनके मार्गदर्शन से विद्यार्थी ज्ञान के साथ संस्कार, नैतिक मूल्य, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना ग्रहण करते हैं। बदलते समय में शिक्षक की भूमिका और अधिक व्यापक हुई है तथा विद्यार्थियों को सक्षम, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

समारोह में महाविद्यालय के शिक्षकगणों का सम्मान किया गया। आयोजन ने गुरु-शिष्य परंपरा की गरिमा को अभिव्यक्त करते हुए महाविद्यालय परिवार में आत्मीयता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया।

अंत में डॉ. पुष्पेंद्र शाह ने आभार व्यक्त करते हुए प्राचार्य, शिक्षकगण, अतिथियों तथा कार्यक्रम की सफलता में सहयोग करने वाले सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

संपादकीय

जर्जर इमारतें गिरती रहीं, तंत्र सोता रहा: आखिर कौन होने देता है ऐसे ह्दसے?

हाल के दिनों में देश भर में जर्जर इमारतों के गिरने या आग लगने के कई ह्दसے सामने आ चुके हैं। बीते जून में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग से बाईस लोगों की मौत हो गई थी। देश में महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक में किराए पर मकान देने का एक बहुत बड़ा उद्योग खड़ा हो गया है। जहां जगह मिले, वहां बहुमंजिला इमारतें बना दी जाती हैं। सरकारी दस्तावेजों में भले ही ऐसी इमारतें आवासीय श्रेणी में पंजीकृत होती हैं, लेकिन इनमें से कई में चिड़ंग गेस्ट (पीजी), होटल और रेस्तरां संचालित किए जाते हैं। जब ये इमारतें जर्जर हो जाती हैं, तो कई दफ्ता भरभराकर गिर जाती हैं या इनमें आग लगने के ह्दसے होते हैं। ऐसी घटनाओं में एफआइआर दर्ज होती है, उसके बाद कुछ इमारतों पर सीलिंग या तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और बाद में सब कुछफिर उसी ढ़र पर लौट आता है।हादसों की कड़ियों में बीते रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास स्थित सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत के ढहने की घटना भी शामिल हो गई है, जिसमें विद्यार्थियों समेत सात लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है, बल्कि यह भी है कि कौन है, जो ऐसा होने दे रहा है?हाल के दिनों में देश भर में जर्जर इमारतों के गिरने या आग लगने के कई ह्दसے सामने आ चुके हैं। बीते जून में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग से बाईस लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलीगंज स्थित एक व्यावसायिक इमारत में आग की घटना में विद्यार्थियों समेत पंद्रह लोगों की जान चली गई थी।खबरों के मुताबिक, सत्य निकेतन में जिस इमारत के गिरने से ह्दसा हुआ, वह काफी पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। इसके बावजूद उसे पीजी के तौर पर किराए पर दिया गया था। जब ह्दसा हुआ, उस वक वहां भूतल पर मरम्मत कार्य चल रहा था। यानी वहां रहने वाले विद्यार्थियों की जान को जानबूझकर जोखिम में डाला गया। पुलिस ने भले ही इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और सरकार ने संबंधित पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन क्या इस कार्रवाई से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि भविष्य में ऐसे ह्दसے की पुनरावृत्ति नहीं होगी?सवाल सिर्फ किसी एक घटना का नहीं है, बल्कि देश भर में उन हजारों जर्जर इमारतों का है, जिनका नियमों को ध्ता बताकर व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े शहरों में किसी इमारत का नक्शा पास होने से लेकर उसके बनने तक एक लंबी विभागीय प्रक्रिया होती है। कई स्तर पर जांच होती है, तब जाकर उसके इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है। इसके बाद भी समय-समय पर उसकी जांच करने का प्रावधान है और अगर वह जर्जर हालत में पाई जाती है, तो उसे असुरक्षित घोषित किया जाता है।

हादसा नहीं, हत्या है ये !दिल्ली में मौत के बाद ही क्यों जागता है सिस्टम?

(नैना गुप्ता)

दिल्ली में सत्य निकेतन ह्दसے के बाद एमसीडी अधिकारियों के निलंबन, इमारत के मालिक की गिरफ्तारी और सरकार के सख्त कार्रवाई के भरोसे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इमारत असुरक्षित थी तो कार्रवाई ह्दसے से पहले क्यों नहीं हुई? दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना ने राजधानी की बिल्डिंग सुरक्षा और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिरती है। मलबे के नीचे दब जाते हैं वे लोग जो इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने आए थे। कोई पढ़ने आया था, कोई नौकरी करने। किराया देकर रह रहे थे यानी उस इमारत के मालिक के लिए वे ग्राहक थे। लेकिन क्या उनके लिए वह इमारत सुरक्षित थी?

अगर जवाब नहीं है तो इसे महज हादसा कहकर आगे बढ़ जाना काफी नहीं है। हादसा तब होता है जब किसी घटना को रोकना नहीं जा सकता। लेकिन जब नियम मौजूद हों, निगरानी के लिए पूरा सरकारी तंत्र मौजूद हो और फिर भी लापरवाही होती रहे तो सवाल हादसे से आगे जाता है। सत्य निकेतन की इस इमारत में पांच फ्लोर बनाए गए थे और हर मंजिल पर चार कमरे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र यहां ऊंचा किराया देकर रह रहे थे। यानी यह कोई सुनसान या बंद पड़ी इमारत नहीं थी। यहां रोज लोग रहते थे, आते-जाते थे और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी इमारत की चारदीवारी के भीतर गुजार रहे थे।

हादसے के बाद एमसीडी के पांच अधिकारियों को सस्पेंडकिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। घायलों

की मदद का भरोसा दिया है। इमारत के मालिक हरिराम बंसल, उसके बेटे और पत्नी को हिरासत में भेज दिया गया है।

राजधानी में हाल के वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले नियम टूटते हैं। फिर शिकायतें या खतरे सामने आते हैं। सिस्टम उन्हें नजरअंदाज करता है। फिर हादसा होता है। लोग मरते हैं। इसके बाद जांच बैठती है, अधिकारी सस्पेंड होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और सरकार सख्त कार्रवाई का भरोसा देती है।कुछ समय बाद कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है।

मालवीय नगर के बीएण्डबी में लगी आग को ही देख लीजिए। वहां भी सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं था बल्कि इस बात का था कि जिस जगह का इस्तेमाल रहने के लिए हो रहा था। वहां सुरक्षा और अनुमतियों के नियमों का पालन किना हुआ था। आग के बाद नियामकीय खामियां सामने आईं और कार्रवाई की बातें हुईं।

ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा तो अभी ज्यादा पुराना भी नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की बेसमेंट में पानी भरने से मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। तब भी एमसीडी से लेकर दूसरे संबंधित विभाग सवालों के घेरे में आए। बेसमेंट, ड्रेनेज और कोचिंग संस्थानों के नियमों को लेकर बड़े-बड़े ऐलान हुए।लेकिन आज भी मूल सवाल वहीं खड़ा है- क्या सरकारें सिर्फ मौत के बाद ही अपनी जिम्मेदारी याद करती हैं? और यह सवाल किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है।

आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उससे पहले कांग्रेस सत्ता में थी। पार्टीयें बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे लेकिन अवैध निर्माण, नियमों की अनदेखी और

सरकारी निगरानी की कमजोरी की समस्या बनी रही।इसलिए, इसे सिर्फ राजनीतिक बहस बनाना आसान रास्ता होगा।असल सवाल सिस्टम की जवाबदेही का है।आखिर एक इमारत पांच मंजिल तक कैसे पहुंचती है? अतिरिक्त कमरे कैसे बनते हैं? एक बेसमेंट ऐसे इस्तेमाल में कैसे आता है जिसका अनुमति नहीं है? किसी जगह पर क्षमता से ज्यादा लोग कैसे रहने लगते हैं? फायर सेफ्टी के इंतजाम कागजों में पूरे और जमीन पर अधूरे कैसे रह जाते हैं?इनमें से कुछ भी अचानक नहीं होता।

हर अवैध निर्माण के पीछे महीनों और वर्षों का समय होता है। हर नियम तोड़ने के पीछे कोई न कोई मौका होता है जब संबंधित विभाग उसे रोक सकता है। हर खतरनाक इमारत हादसे से पहले ही खतरनाक होती है।फिर कार्रवाई हादसे के बाद ही क्यों? क्योंकि यहां एक खतरनाक आर्थिक गणित भी काम करता है।बिल्डिंग मालिक के लिए एक अतिरिक्त मंजिल मतलब अतिरिक्त किराया। एक कमरे में ज्यादा बेड मतलब ज्यादा कमाई। नियमों पर खर्च न करना मतलब ज्यादा मुनाफा। लेकिन इस मुनाफे में सुरक्षा की कीमत शामिल नहीं होती।

वह कीमत आखिर में कौन चुकाता है?: एक छात्र जो अपने माता-पिता की उम्मीदों के साथ दिल्ली आया था।एक परिवार जिसने सोचा था कि उनका बच्चा सुरक्षित शहर में रहकर पढ़ाई करेगा।और वह आम नागरिक, जिसे यह उम्मीद होती है कि सरकार ने जिस जगह को लोगों के रहने और काम करने के लिए खुला छोड़ रखा है, वहां कम से कम बुनियादी सुरक्षा तो होगी।नागरिकों से हर नियम मानने की उम्मीद की जाती है। फिर नियम लागू कराने वालों से उसी गंभीरता की उम्मीद क्यों नहीं की जानी चाहिए? उसी निकेतन के इस हादसे के बाद पांच अधिकारियों का

निलंबन हो गया। मालिक पकड़ा गया। जांच होगी। रिपोर्ट आएगी। शायद कुछ और गिरफ्तारियां भी हों।लेकिन अगर इसके बाद भी दिल्ली के हजारों पीजी, हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, बीएण्डबी और दूसरी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था उसी तरह चलती रही तो यह कार्रवाई सिर्फ एक हादसे को फाड़ल बंद करेगी, समस्या की नहीं।दिल्ली में ऐसे सभी भवनों का नियमित सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए जहां बड़ी संख्या में छात्र और दूसरे लोग रहते हैं। स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण का मिलान हो। फायर सेफ्टी और बेसमेंट के इस्तेमाल की नियमित जांच हो। शिकायतों पर कार्रवाई की समयसीमा तय हो। और सबसे महत्वपूर्ण- लापरवाही की जिम्मेदारी सिर्फ उस कमर्चारी तक सीमित न हो जो मौके पर तैनात था। जिस स्तर पर निगरानी विफल हुई, जवाबदेही भी वहां तक पहुंचे।क्योंकि निलंबन किसी की जान वापस नहीं ला सकता।इंसानी जान जाने के बाद सिस्टम की सक्रियता, सिस्टम की सफलता नहीं होती। असली सफलता तब होगी जब सिस्टम खरोंे की मौत में बदलने से पहले पहचान ले।सत्य निकेतन के मलबे से सिर्फ शव नहीं निकले हैं। इस हादसे ने दिल्ली के प्रशासन के सामने आईना रख दिया है।अब देखना यह है कि सरकार उस आईने में सिर्फ दोषी ढूंढती है या अपनी व्यवस्था की खामियां भी देखती है। क्योंकि अगली इमारत कब गिरेगी, अगली आग कहां लगेगी, अगला बेसमेंट कब जानलेवा बनेगा- यह कोई नहीं जानता।लेकिन इतना जरूर तय किया जा सकता है कि अगली मौत के बाद जागने के बजाय दिल्ली का सिस्टम इस बार पहले जागे। वरना हर बार यही कहना पड़ेगा- यह हादसा नहीं था। इसे रोका जा सकता था। (यह लेखिका के अपने विचार हैं)

साक्षरता का राफ़्त- 2030 की समय सीमा से पहले क्या पूरा हो पाएगा लक्ष्य?

(राजेंद्र जोशी)

वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत को जल्द साक्षर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत पूरे देश में साक्षरता का जनआंदोलन शुरू किया गया, जिसे संपूर्ण साक्षरता अभियान का नाम दिया गया।

आजादी के समय भारत ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का सपना नहीं देखा था, बल्कि एक ऐसे राह की कल्पना की थी, जहां हर नागरिक पढ़-लिख सके, अपने अधिकारों को समझ सके और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन सके। यह सपना उस समय और भी बड़ा था, जब वर्ष 1951 की पहली जनगणना में देश की साक्षरता दर महज 18.3 फीसद थी। यानी आजाद भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अक्षरों के आलोक से वंचित था। मगर राह निर्माण की उस सुबह यह विश्वास था कि शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक दिन पूरा भारत साक्षर होगा, जो शिक्षास्तिर राह की मजबूत नींव तैयार करेगा। आजादी के करीब आठ दशक बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उपलब्धियों के साथ एक बेचैन करने वाला सवाल भी सामने खड़ा दिखाई देता है- आखिर भारत कब पूरी तरह साक्षर एवं शिक्षित होगा? हालांकि, साक्षरता के क्षेत्र में देश ने लंबी यात्रा तय की है। वर्ष 1951 में 18.3 फीसद से बढ़कर 2011 में देश की साक्षरता दर 74.04 फीसद हो गई। वर्ष 2001 में यह 64.83 फीसद थी। यानी एक दशक में 9.21 फीसद की वृद्धि हुई। महिला साक्षरता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ और 2001 के 53.67 फीसद से बढ़कर 2011 में यह 65.46 फीसद हो गई। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत को जल्द साक्षर बनाया जाएगा। इसके

अंतर्गत पूरे देश में साक्षरता का जनआंदोलन शुरू किया गया, जिसे संपूर्ण साक्षरता अभियान का नाम दिया गया। मगर राष्ट्रीय औसत की चमक के पीछे राज्यों के बीच की असमानता आज भी संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य के लिए बड़ी चुनौती है। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता थी- सरकार के साथ समाज की भागीदारी। स्वयंसेवक, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, प्रशासन और आम नागरिक इस अभियान का हिस्सा बने। वर्ष 1990 के दशक में संपूर्ण साक्षरता अभियान ने देश के अनेक हिस्सों में उम्मीद जगाई। सरकारी मशीनरी और सामाजिक संगठनों की साझेदारी से यह साबित हुआ कि इच्छाशक्ति, जनभागीदारी और स्थानीय नेतृत्व मिल जाए, तो निरक्षरता जैसी बड़ी चुनौती को भी पीछे छोड़ा जा सकता है। इस अभियान की सबसे बड़ी प्रेरक मिसाल केरल बना। 18 अप्रैल, 1991 को केरल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल की उपलब्धि ने देश को यह भरोसा दिया कि संपूर्ण साक्षरता कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। मगर सवाल है कि जब एक राज्य पूर्ण साक्षर हो गया, तो अगले तीन दशक में देश के सभी राज्य उस मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच सके? दरअसल, साक्षरता अभियान के शुरुआती दौर की जनभागीदारी धीरे-धीरे कमजोर हुई है। साक्षरता को निरंतर सामाजिक आंदोलन बनाए रखने के बजाय कई जगह यह सरकारी कार्यक्रमों और आंकड़ों तक सीमित होती गई। निरक्षर वयस्कों की पहचान, उन्हें नियमित रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, सीखने के बाद उनकी शिक्षा को जारी रखना और नई पीढ़ी को स्कूल से बाहर न होने देना, इन सभी कड़ियों को एक साथ मजबूत करने की आवश्यकता थी। साक्षरता केवल किसी व्यक्ति का अपना नाम लिख लेने तक सीमित नहीं हो सकती।

चीन जिस प्रकार ‘सलामी स्लाइसिंग’ जैसी रणनीतियों के माध्यम से दो कदम आगे चलकर एक कदम पीछे हटने की नीति अपनाता है, वह किसी भी पड़ोसी देश के लिए एक चुनौती ही है। भारत ही नहीं, बल्कि अन्य पड़ोसी देश भी उसकी इस नीति से परिचित और परेशान हैं। इसके बावजूद अगर भारत अपने सीमा विवादों के समाधान के लिए आक्रामक साधनों के विपरीत शांतिपूर्ण साधनों को वरीयता देता है, तो वह संघर्षपूर्ण विश्व में एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है।

(श्रद्धा त्रिषि)

चीन जिस प्रकार ‘सलामी स्लाइसिंग’ जैसी रणनीतियों के माध्यम से दो कदम आगे चलकर एक कदम पीछे हटने की नीति अपनाता है, वह किसी भी पड़ोसी देश के लिए एक चुनौती ही है।

हाल ही में बीजिंग में संपन्न हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस वार्ता ने इस बात को और भी अधिक पुष्ट कर दिया कि दोनों देशों के बीच शीघ्र सीमा निर्धारण आपसी विश्वास बहाली के लिए कितना अधिक जरूरी है। साथ ही यह वार्ता भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों के समक्ष इस चुनौती को भी रेखांकित करती है कि चीन की विस्तारवादी नीति से किस प्रकार निपटा जाए।

चीन जिस प्रकार ‘सलामी स्लाइसिंग’ जैसी रणनीतियों के माध्यम से दो कदम आगे चलकर एक कदम पीछे हटने की नीति अपनाता है, वह किसी भी पड़ोसी देश के लिए एक चुनौती ही है। भारत ही नहीं, बल्कि अन्य पड़ोसी देश भी उसकी इस नीति से परिचित और परेशान हैं। इसके बावजूद अगर भारत अपने सीमा विवादों के समाधान के लिए आक्रामक साधनों के विपरीत शांतिपूर्ण साधनों को वरीयता देता है, तो वह संघर्षपूर्ण विश्व में एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से विवादों का समाधान भारत की सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप है, लेकिन इसके साथ ही चुनौती यह भी है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अखंडता को किस प्रकार सुनिश्चित रखा जाए।

इस विशेष प्रतिनिधि वार्ता में दोनों देशों के बीच आठ-बिंदु परिणाम दस्तावेज पर सहमति बनी, जिसमें दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की व्यापक समझ और सीमाई प्रबंधन पर जोर दिया है। इस वार्ता के बाद जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, उसमें जमीनी स्तर पर किसी भी मुद्दे से निपटने के लिए कुटनीतिक और सैन्य संचालनों को विकसित करने की बात कही गई है।

इसमें सलाह और सहयोग के लिए कार्यकारी प्रविधि पर जोर दिया गया है। इस आठ-बिंदु के दस्तावेज के ही एक बिंदु में भारत-चीन सीमा पर दो और सीमा कार्मिक बैठक स्थल निर्धारित करने की बात कही गई है। वर्तमान में पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर में इस तरह के पांच ऐसे मिलाप स्थल हैं, जिनमें लद्दाख में दो- दौलत बग ओल्दी और चुशुल, सिक्किम में एक- नाथुला और अरुणाचल प्रदेश में दो- किचिब और बूम ला में हैं।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में इन मिलाप स्थलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है,

भारत-चीन सीमा विवाद- विश्वास बहाली की राह में चीन पर भरोसे का संकट

जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के प्रमुख अफसर आपस में स्थानीय और समय-समय पर उभरे मुद्दों पर बात करते हैं, जिससे गलतफहमियों का दायरा कम हो जाता है और सीमा रक्षक सेनाओं में आत्मविश्वास का संचार होता है।

भारत ने 1996 से ही, जब से दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के उपाय किए गए, वास्तविक नियंत्रण रेखा के



बेहतर निर्धारण पर जोर दिया है। विश्वास बहाली किसी भी अप्रिय घटना के बाद बहुत जरूरी होती है। सीमा पर कोई एक भी अवांछनीय घटना सामान्य रिश्तों को पटरी से उतार देती है और उन्हें दशकों पीछे ले जाती है। आपसी रिश्तों में कड़वाहट को दूर करने के लिए विश्वास बहाली बहुत जरूरी हो जाती है।

यह बात भारत-चीन संबंधों के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है। सीमा पर चीन की संदेहास्पद गतिविधियां, चाहे वह डोकलाम हो या गलवान, इसके प्रति संदेह को और भी अधिक मजबूती दे देती हैं। पिछले साल तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गलवान के बाद उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए संकल्प व्यक्त किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के

साथ चीनी विदेश मंत्री की यह बैठक इसी क्रम में एक और प्रयास था, इस आशा के साथ कि इससे फिर संस्थगत स्तर पर सीमा विवाद संबंधी वार्ता को गति दी जा सकेगी।

गौरतलब है कि बीजिंग में हुई यह ‘विशेष प्रतिनिधि’ स्तर की वार्ता अपने क्रम में पच्चीसवीं वार्ता थी। इस वार्ता में राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ सैन्य अफसर भी भाग लेते हैं, जिसमें यह प्रयास किया जाता है कि सीमा विवाद की जटिलता को देखते हुए तकनीकी और कठोर दृष्टिकोण के बजाय राजनीतिक स्तर पर क्या कुछ नया और रचनात्मक समाधान खोजे जा सकते हैं। इन्हीं वार्ताओं के क्रम में दोनों देश 2005 में तकनीक का मुद्दा हो या गिलगित-बाल्टिस्तान पर सहमत हुए, जो सीमा विवाद के समाधान के लिए आधार प्रदान करेंगे।

प्रश्न यह है कि चीन के तमाम भारत विरोधी प्रयासों को देखते हुए क्या भारतीय जनता में विश्वास बहाली संभव हो पाएगी। क्या भारतीय जनता चीन के नापाक इरादों को दर्किनार कर फिर सामान्य संबंधों के लिए तैयार हो पाएगी? चीन जिस तरह पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन देता है, वह किसी से छिपा नहीं है। कश्मीर का प्रश्न हो या आतंकवाद पर रोक लगाने की बात, परमाणु राजनीतिक मानक एवं दिशानिर्देशी सिद्धांत पर सहमत हुए, जो सीमा विवाद के समाधान के लिए आधार प्रदान करेंगे।

गौरतलब है कि चीन की विदेश नीति जिस सैन्य दर्शन से प्रेरित होती है, उसमें ‘डिसीविंग द हैव्सन टू क्रॉस द ओशन’ एवं ‘मेकिंग अ साउंड इन द ईस्ट देन स्ट्राइक वेस्ट’ जैसी रणनीतियां बहुत आम हैं और चीन के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों में देखी भी जा सकती हैं। गौरतलब है कि चीन इसी तरह अपनी समुद्री सीमा में भी विस्तार करता रहा है। चाहे वह कृत्रिम रूप से द्वीप बनाना हो या समुद्र में सैनिक चौकी स्थापित

करना हो, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में उसकी विस्तारवादी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हैं।

दक्षिण चीन सागर में वह अपने ऐतिहासिक दावे के अंतर्गत जिस नव-बिंदु रेखा के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों के काफी बड़े समुद्री हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, उसे संयुक्त राष्ट्र का समुद्री सीमा न्यायिक आयोग 2016 में पूरी तरह से खारिज कर चुका है। इस परिदृश्य में विश्वास का संकट भारत-चीन आपसी संबंधों के सामान्यीकरण के किसी भी प्रयास को निष्फल सिद्ध कर देता है।

यह इस समस्या को भी रेखांकित करता है कि सीमा को बहुत अधिक समय तक असुलझा नहीं रहने दिया जा सकता। अतीत में राजीव गांधी सरकार ने समय की मांग को देखते हुए सीमा विवाद को परे रखकर दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा दिया था। उस समय यह कल्पना की गई थी कि व्यापार संबंधों में आई मजबूती सीमा विवाद को सुलझाने में मदद प्रदान कर सकती है। वास्तव में देखा जाए, तो भारत-चीन संबंधों में सीमा को असुलझा रहने देने से जटिलता और अधिक बढ़ी ही है।

संदेहास्पद संबंधों के परिदृश्य में व्यापार संबंध बढ़ाने से परिणाम यह हुआ है कि व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक निवेश इस तरह के व्यापार घाटे को कम करने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है, जिसमें दोनों देश मिलकर संयुक्त रूप से उत्पादन करते हैं, लेकिन भारतीय नीति निर्माता चीन के संशक्ति व्यवहार के कारण भारत में चीनी निवेश को अनुमति नहीं दे पाते हैं।

अब देखना यह है कि ‘विशेष प्रतिनिधि’ स्तर की वार्ता दोनों देशों के आपसी संबंधों को कितना बल प्रदान कर पाती है। जिस प्रकार पूरी दुनिया दो युद्धों की विभीषिकाओं से जुड़ा रही है, ऐसे समय में अगर ये दो हिमालयी शक्तियां वार्ता के माध्यम से अपने विवाद निपटा पाती हैं, तो यह वैश्विक शांति के लिए एक अमूल्य योगदान होगा। (यह लेखिका के अपने विचार हैं)

वर्ग पहेली 6208											
1		2		3		4					
		5				6					
7	8			9							
10				11		12		13			
14		15				16					
				17		18					
								20			
19											
21						22					

संकेत: बाएं से दाएं

- बायन लवार फारले ऐसे क्रिकेटर है जिसने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 400 रन बनाए, यह स्कोर इत देश के खिलाफ बनाए थे (3)
- 14 वीं-15 वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत जिनके निरूनमीमा नामक जुगलहे रचित ने पाला था (3)
- काव्य गार्मंड, रस पान करने वाला (3)
- गाए जाने वाले केसमें (2)
- जागृत होना, नींद से उठना (3)
- जीवन, शिष्टी (3)
- मेरा या मेरी (संस्कृत)(2)
- ब्रह्म, विद्या, आगे की ओर (2)
- छोटा, निचरा, तीन प्रकार के प्राणायामों से एक (2)
- वायुयान में चालक के बैठने की सीट (4)
- अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला, स्वैच्छाचारी (4)
- एक बार संस लेने का समझ, कल (2)
- यह जातका का पुराना नाम है (2)
- जिसने कौटिल्य घटना अपने आँखों से देखी हो, सावर (3)
- अभि बूझने का वंश (4)
- ऊपर से नीचे

- इंतजाम करने वाला (6)
- भयभीत होना, खौफ जगज होना (3)
- क से ह तक की वर्णमाला (4)
- पुराणनृसर सात लोकों में से छठे लोक का नाम जहां की भूमि पयरीही है (4)
- खुराश्व, सुगंध, महक (3)
- विहार के इत शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था (3)
- किसी द्रव्य या पानी में घुलने वाला (5)
- पिता का पिता, दादा, बाबा (4)
- अनुराग, प्रेम, लालसा, इच्छा (2)
- संभव है कि, कदाचित (3)
- अधीन्य, उपचार (2)
- कोआ पत्नी, काम (2)

वर्ग पहेली 6207 का हल											
ला	ही	र		ब	र	ग	द				
म	ज	ना		ह	मा	रा					
ब		ना	म	क		रा	पी				
दी	न		स	ना	थ		प				
		म	ह	ल		प	ह	ल			
ता	क	ना	पा	क							
	खा	ब		ता	ना	बा	ना				
शा	र	दा		ल		द	ल				

आज का राशिफल



मेघ

आज धन की स्थिति किसी अचानक लाभ से नहीं, बल्कि नियम से बनाई गई योजना से बेहतर होगी। पर या परिवार की सुख-सुविधाओं पर खर्च का मन हो सकता है। ऐसे में अपनी असली जरूरत और अचानक उठी इच्छा का अंतर समझें। किसी के कदम भरसेमंद दिखने पर ही ऐसे से जुड़ा बड़ा निर्णय न लें।



मिथुन

नए मौके और जल्दबाजी से बचाव आज एक साथ कमाई के कई रास्ते मन में आ सकते हैं। आपकी उत्सुकता नए मौके तलाशने में मदद करेगी, पर जल्दबाजी में कोई खरीदारी या जोखिम भरा निर्णय न लें।



सिंह

आज पैसों से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। ऐसा लग सकता है कि कुछ पुरानी चीजें अब पहले जैसी खुशी नहीं दे रही। अपनी कमाई का सही उपयोग करें और केवल दूसरों के सामने पहचान बनाए रखने के लिए पैसा खर्च न करें।



वृष

आज का दिन पुरानी बचत संभालने और धन को सुरक्षित रखने के लिए सही है। हर महीने होने वाले खर्चों, पुरानी योजनाओं और बचे हुए भुगतानों को जांचना कायदेमंद रहेगा। डर की वजह से अत्यधिक कंजूसी भी न करें और बिना सोचे-समझे किसी अनजान जगह धन लगाने का जोखिम भी न उठाएं।



कर्क

आज धन के मामलों पर पूरा ध्यान रहेगा। अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने को लेकर मन में अच्छी उम्मीद रहेगी। बचत और परिवार के भविष्य की योजना बनाने का सही समय है। अति-उत्साह में आकर तय बजट से ज्यादा खर्च करने से बचें। आज अपने लक्ष्यों से मन का खास जुड़ाव महसूस होगा।



कन्या

आज पैसों के मामले में सटीक सोच बनी रहेगी। आप किसी पुरानी भूल, फालतु खर्च या छूटे हुए मौके को आसानी से पकड़ लेंगे। बजट बनाना और पुराने खातों को देखना फायदेमंद रहेगा। केवल अनुमान लगाने के बजाय असली आंकड़ों और लिख

संक्षिप्त

समाचार

‘आखिर कब तक’ सत्य निकेतन हादसे के बाद अभविप का डीयू में सेफ्टी मार्च, पीजी के सुरक्षा ऑडिट की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। सत्य निकेतन हादसे के विरोध और छात्र सुरक्षा की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मंगलवार को डीयू के नार्थ कैंपस में स्टूडेंट सेफ्टी मार्च निकाला। आखिर कब तक के नारे के साथ निकाले गए मार्च में डीयू के विभिन्न कालेजों के बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। मार्च रावबी ग्राउंड से शुरू होकर आर्ट्स फैंकल्टी पहुंचा। एबीवीपी ने मांग की कि दिल्ली विश्वविद्यालय और छात्र बहुल इलाकों में संचालित सभी पीजी आवासों का तत्काल सुरक्षा और संरचनात्मक आडिट कराया जाए। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले पीजी संचालकों और भवन मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन ने डीयू में नए छात्रावास बनाने और मौजूदा छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने की भी मांग की, ताकि छात्र असुरक्षित पीजी और किराये के भवनों में रहने को मजबूर न हों। एबीवीपी ने सत्य निकेतन हादसे को प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताते हुए जिम्मेदारी तय करने और एमसीडी आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि छात्र भविष्य बनाने के लिए दिल्ली आते हैं, उन्हें सुरक्षित आवास के अभाव में जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। अब आश्वासन नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि सत्य निकेतन हादसा बदलाव का आधार बनना चाहिए। प्रत्येक पीजी का आडिट और उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

दिल्ली महापौर कार्यालय को नौवीं बार मिली बम की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर कार्यालय को मंगलवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। लगातार नौवीं बार धमकी मिलने से निगम अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही महापौर कार्यालय की ओर से दिल्ली पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा-व्यवस्था सक्रिय करते हुए कार्यालय परिसर की सघन जांच की। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने महापौर कार्यालय के संवेदनशील स्थानों, प्रवेश और निकास द्वार समेत पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिला तो इसे भी हावस करार दिया गया। मध्य जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह 10:11 बजे महापौर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकलकर्मियों, डाग स्वचायड और अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ परिसर खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। इससे पहले भी आठ बार इसी तरह बम धमाके की धमकियां मिल चुकी हैं। लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए महापौर कार्यालय की ओर से पूर्व में दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा गया था। पत्र में धमकियों को विस्तृत जांच कर आरोपितों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।

एयर इंडिया का प्लेन हवा में अटका, विमान में सवार थे राहुल गांधी

नई दिल्ली। विमान हादसों की लगातार सामने आ रही खबरों के बीच अब एक और घटना ने चिंता बढ़ा दी है। इस बार मामला लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विमान से जुड़ा है। दरअसल, मंगलवार यानी 8 सितंबर को राहुल गांधी का दिल्ली से लखनऊ लेकर आ रहे एयर इंडिया के विमान की लैंडिंग के वक्त अचानक मुश्किल खड़ी हो गई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तेज हवा के दबाव के चलते पावलट को विमान उतारने के लिए दो बार कोशिश करनी पड़ी। पहले प्रयास में लैंडिंग नहीं हो सकी, जिसके बाद विमान करीब 10 मिनट तक हवा में चक्कर काटता रहा। आधिकारिक दूसरे प्रयास में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों की सांसें अटकती रहीं।

ब्रिक्स सम्मेलन पहले दिल्ली ‘खाली’ कराने की कवायद, फुटपाथों से बेघर-भिखारी और रेहड़ी वाले हटाए जा रहे

नई दिल्ली, एजेंसी। आगामी ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों के बीच राजधानी लुटियंस दिल्ली से लेकर प्रमुख सड़कों को शानदार रूप देने का काम जोरों पर है। इस सुंदरीकरण और सुरक्षा कवायद के बीच सड़कों और फुटपाथों पर रहने वाले बेघर, भिखारियों, नशेड़ी तथा सामान बेचने वालों को भी हटाने का क्रम जारी है। कनाट प्लेस, इंडिया गेट, भारत मंडपम, खान मार्केट, मंडी हाउस, निजामुद्दीन, व राजघाट और लाल किले जैसे प्रमुख इलाकों से बेघरों और भिखारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस, ड्राइसि, एमसीडी और एनडीएमसी का संयुक्त अभियान तेजी से चल रहा है। प्रशासनिक दवाों के मुताबिक यह कार्रवाई मेहमानों और वीवीआइपी रुटों की सुरक्षा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि

दिल्ली में महिला ने रैपिडो बाइक बुक की, पहुंची दूसरे नंबर की स्कूटी; राइड-शेयरिंग एप्स की सुरक्षा पर उठे सवाल

नईदिल्ली, एजेंसी। 31 अगस्त को यशोभूमि से द्वारका सेक्टर-21 जाने के लिए एक महिला यात्री ने रैपिडो बाइक बुक की। ऐप पर दिख रहे वाहन नंबर से मौके पर पहुंची स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था। पृच्छने पर राइडर कभी गाड़ी खराब होने तो कभी स्कूटी के चार्जिंग पर लगे होने का बहाना बनाने लगा। मना करने के बावजूद वह जबरन बैठने का दबाव बनाता रहा और मजबूरी में महिला को सफर करना पड़ा। महिला का सवाल है कि अनहोनी होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी और यात्री पहचान कैसे सुनिश्चित करे। यह अकेला मामला नहीं है, राजधानी और आसपास रोजाना कई यात्री इस डर से जूझ रहे हैं।

नंबर ही नहीं, बाइक का माडल भी बदला : बरकुर निवासी अंजना शा का अनुभव वाहन नंबर बदलने से भी आगे का है। बुकिंग के समय ऐप पर जिस वाहन की जानकारी दी गई थी, पिकअप प्वाइंट पर उसकी जगह दूसरा माडल और वाहन लेकर राइडर पहुंचा। अंजना बताती हैं कि यात्री ऐप की जानकारी के आधार पर ही पहचान करता है। बिना किसी पूर्व सूचना के पूरा वाहन बदल जाने से यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सामने आया वाहन उसी बुकिंग का हिस्सा है या नहीं।

ओला आटो में भी सामने आया ऐसा ही मामला : नोएडा निवासी दीप्ति ने ओला से आटो बुक किया। पिकअप पर पहुंचे आटो का



नंबर ऐप की जानकारी से अलग था। चालक ने आटो खराब होने की बात कही। दिन का समय और जल्दबाजी के कारण दीप्ति ने सफर तो कर लिया, लेकिन उनका कहना है कि रात के समय यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। ऐसे में वास्तविक वाहन की ट्रैकिंग कैसे संभव होगी।

सुरक्षा पर बड़ा खतरा, ट्रैकिंग व पैनिक बटन बेअसर : अगर मौके पर पहुंचा वाहन ऐप में दर्ज डेटा से अलग है, तो ऐप का लाइव ट्रैकिंग और एसओएस/पैनिक बटन फीचर तकनीकी रूप से बेअसर हो जाता है, क्योंकि आन-रिकार्ड वह गाड़ी चल ही नहीं रही होती। किसी वारदात की स्थिति में पुलिस रिकार्ड में ऐप पर दर्ज पुराना नंबर आएगा, जबकि अपराधी

दूसरी गाड़ी से आसानी से फरा हो चुका होगा। दूसरी ओर, बिना परमिट या अलग वाहन से सवारी खोने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन जक्ती का नियम है, लेकिन परिवहन विभाग की हिलाई से ऐसे चालकों के हासले बुलंद हैं। यशोभूमि में महिला यात्री से हुई घटना के बारे में द्वारका क्षेत्र के परिवहन अधिकारी से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिला।

रैपिडो ने जताया खेद, राइडर सस्पेंड : सुरक्षा व्यवस्था और वाहन बदलने के नियमों पर रैपिडो और ओला से जवाब मांगा गया। रैपिडो ने ईमेल के जरिए खेद जताते हुए बताया कि संबंधित राइडर को प्लेटफार्म से स्थायी रूप से निलंबित

(ब्लैकलिस्ट) कर दिया गया है, ताकि वह भविष्य में दोबारा न जुड़ सके। वहीं, ओला की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

यात्री अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें : नंबर व माडल मिलाएं : ऐप में दिख रहे नंबर प्लेट और वाहन के माडल का मिलान किए बिना कभी भी न बैठें।

राइड तुरंत रद्द करें: अंतर होने पर राइडर के दबाव में न आएँ, तुरंत उचित विकल्प चुनकर राइड कैंसिल करें।

स्क्रीनशाट व लोकेशन: बुकिंग विवरण का स्क्रीनशाट रखें और स्वजन के साथ लाइव लोकेशन जरूर शेयर करें।

उपभोक्ता चाहते हैं पैकेट पर साफ दिखे ‘ज्यादा चीनी-नमक-फैट’ की चेतावनी, सर्वे का बड़ा खुलासा



नई दिल्ली, एजेंसी। पैकेटबंद खाद्य और पेय पदार्थों में चीनी, नमक या फैट की मात्रा ज्यादा है तो इसकी जानकारी उपभोक्ताओं को पैकेट के सामने ही साफ-साफ मिलनी चाहिए। लोकल सर्वेल्स के एक सर्वे में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने कहा कि किसी उत्पाद में इनमें से एक भी चीज तय सीमा से ज्यादा हो तो उस पर स्पष्ट चेतावनी होनी चाहिए।

उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रस्तावित नियमों के दूसरे चरण का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।

एफएसएसएआई ने 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सामने वाले हिस्से पर मिलाई गई चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा होने पर तस्वीर के जरिए चेतावनी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के तहत पैकेट पर लाल रंग के हेक्सागोनल आकार के निशान में ‘ज्यादा चीनी’, ‘ज्यादा नमक’, ‘ज्यादा फैट’ या

‘बहुत ज्यादा मीठा पेय’ जैसी चेतावनी दी जाएगी। इसे दो चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। पहले चरण में चेतावनी उन उत्पादों पर लागू होगी, जिनमें मिलाई गई चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट में से कम से कम दो चीजें तय सीमा से ज्यादा हों। कुछ मीठे पेय भी इसके दायरे में आएंगे। वहीं, अगर किसी उत्पाद में इन तीन में से सिर्फ एक चीज ज्यादा है, तो प्रस्ताव के दूसरे चरण तक उस पर चेतावनी लेबल नहीं लगाने की बात कही गई है। उपभोक्ता चाहते हैं हर ज्यादा मात्रा की जानकारीसर्वे में शामिल ज्यादातर उपभोक्ताओं ने इस व्यवस्था को असहमति जताई। उनका कहना था कि किसी उत्पाद में सिर्फ चीनी, नमक या फैट में से एक की मात्रा भी ज्यादा है तो इसकी जानकारी पैकेट पर साफ तौर पर दी जानी चाहिए। इसे नियम के दूसरे चरण तक टालना नहीं चाहिए। सर्वे में 23,516 प्रतिक्रियाएं मिलीं। इनमें 88 प्रतिशत लोगों ने कहा कि चेतावनी लेबल इतना बड़ा और स्पष्ट होना चाहिए कि उसे पैकेट के सामने से आसानी से पढ़ा जा सके।

डीयू के हजारों छात्रों के सामने हॉस्टल संकट, एनएचआरसी ने दिल्ली सरकार-GC को 15 अक्टूबर तक मांगी कार्ययोजना

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में दाखिला लेने के बाद भी हजारों छात्रों के सामने रहने की जगह का संकट बना हुआ है। खासकर दिल्ली से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किराफयती छात्रावास नहीं मिलने के कारण महंगे पीजी और निजी किराये के मकानों का सहारा लेना पड़ रहा है। छात्रावासों की इस कमी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीर मानवाधिकार का मुद्दा मानते हुए अब दिल्ली सरकार और यूजीसी को जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एनएचआरसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ समन्वय कर छात्रावासों की वास्तविक कमी का आकलन करने और उसे दूर करने की ठोस, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने



का निर्देश दिया है। आयोग ने साफ किया है कि महज नए छात्रावास बनाने का आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा। मौजूदा छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने, नवीनीकरण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ नए छात्रावासों की जरूरत भी तय करनी होगी। आयोग ने कालेज-वार छात्रावास की जरूरत का आकलन करने को भी कहा है। इसके साथ प्रस्तावित कार्य, संस्थागत एवं वित्तीय जिम्मेदारी और प्रत्येक काम को पूरा करने की समय-सीमा भी तय करनी होगी। मुख्य सचिव और

की उपलब्धता बेहद कम है। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षित और किराफयती आवास की होती है। महंगे पीजी का खर्च उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है और कई छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है।

30 सितंबर 2025 को एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानुनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट समय पर नहीं मिलने पर आयोग को रिमाइंडर जारी करना पड़ा। बाद में डीयू ने अपना जवाब दाखिल किया। डीयू ने बताया कि उसके स्नातक कार्यक्रम 65 घंटा और संबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित होते हैं। डीयू ने बाहर से आने वाले छात्रों की आवास संबंधी कठिनाइयों और अतिरिक्त छात्रावास सुविधाओं की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

मैं जिंदा हूं पर वोटर लिस्ट में मर गई’, दिल्ली में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट की गलतियों से खड़े हुए कई सवाल



नई दिल्ली, एजेंसी। मैं 71 साल की हूँ, बीमार जरूर हूँ लेकिन जिंदा हूँ। अस्पताल में इलाज चल रहा है, फिर भी चुनाव आयोग के कागजों में मुझे मृत घोषित कर दिया गया। यह दर्द है जगदंबा कैप की रहने वाली विरमा देवी का है। एसआईआर के बाद जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ियों ने कई नागरिकों के मताधिकार पर संकट खड़ा कर दिया है। राजौरी पहाड़ी के रहने वाले सतपाल सिंह की व्यथा भी कुछ अलग नहीं है। वे बताते हैं कि 1980 के दशक से उनका नाम वोटर लिस्ट में रहा है। इस बार परिवार के सभी सदस्यों के नाम सूची में बरकरार हैं, लेकिन उनका नाम गायब है।

उनके अनुसार प्री-मैपिंग के दौरान ही उनका नाम काट दिया गया। जब वे कारण जानने चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बीएलओ ने अपनी गलती मानते हुए नाम दोबारा जोड़ने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन प्रक्रिया कब पूरी होगी, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। मंगलवार को वोटर अधिकार मंच की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में ऐसे दर्जनों फ़ैलओ ने अपना मतदाता सूची को आधार मानकर इन सभी प्रभावित नागरिकों के नाम ड्राफ्ट रोल में तुरंत बहाल किए जाने चाहिए।

ऐसे लोग आए सामने : पुष्पा (जगदंबा कैप) : वर्ष 2025 में मतदान करने और सालों से एक ही जगह रहने के बावजूद नाम काटकर स्थानांतरित दिखा दिया गया।

पूनम (चिल्ला खादर) : आरोप है कि बीएलओ के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें स्ट्रुक् का फार्म तय सहेया नहीं कराया गया। कमल (दरियागंज जेजे बेला स्टेट) : क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के बावजूद मतदाता वहीं रह रहे थे और 500 से अधिक फार्म भरे गए थे। इसके बावजूद बूथ संख्या 33 (अब 38) के 729 मतदाताओं में से 728 को स्थायी रूप से स्थानांतरित दिखा दिया गया और केवल एक का नाम सूची में रखा गया।

नाजनीन (मंगोलपुरी) : चाचा के मकान का स्थायी पता होने के कारण नाम जोड़ने में अड़चन पैदा की गई। काफी शिकायतों के बाद नाम शामिल हो सका। प्रेसवार्ता में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि बीएलओ और अधिकारियों की गलती के कारण जिन वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनसे दोबारा फार्म- 6 और घोषणा पत्र मांगना पूरी तरह अनुचित है। वर्ष 2025 की मतदाता सूची को आधार मानकर इन सभी प्रभावित नागरिकों के नाम ड्राफ्ट रोल में तुरंत बहाल किए जाने चाहिए।

‘बदला नहीं, न्याय चाहिए’, मणिपुरी संगीतकार विक्रम की पत्नी बोलीं- नहीं चाहती किसी और परिवार के साथ ऐसा हो

नईदिल्ली, एजेंसी। जिस घर में गिटार की मधुर धुन गुंजा करती थी, वहां अब सन्नाटा है। मणिपुर के संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की मौत ने पत्नी जोशना चोंगथम और पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मणिपुर भवन में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए जोशना ने कहा कि हम विक्रम की मौत का बदला नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं, ताकि किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। इन अल्फाजों के साथ ही भावनाओं के सैलाब ने आंखें नम कर दीं। रूंधे गले से बताया कि विक्रम को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्हें मणिपुर ही नहीं बंगाल, असम और उत्तर पूर्व के राज्यों के लोगों का भी प्यार मिला था। जोशना ने कहा कि उनके परिवार ने जो खोया है, उसे वापस नहीं पाया जा सकता। लेकिन वह चाहती हैं कि इस घटना के बाद ऐसी स्थिति दोबारा किसी परिवार के सामने न आए। किसी और पत्नी को अपने पति को इस तरह न खोना पड़े और किसी बच्चे को अपने पिता के बिना बड़ा न होना पड़े। हम विक्रम को न्याय मिलने



तक संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े लोगों का आभार जताया। साथ ही लोगों से परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की। कहा परिवार अभी गहरे सदमे में है और इस मुश्किल घड़ी में उन्हें शांति के साथ शोक मनाने का समय चाहिए। विशेष अदालत में केस चलाने की सिफारिश करेगी सरकार: हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने मंगलवार को मणिपुरी गायक चोंगथम विक्रम सिंह के परिवार से मुलाकात की। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूरी दिल्ली शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन इसका कोई नस्लीय कोण नहीं है। मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करता हूँ।

5 साल में 32,596 मौतों का जिम्मेदार कौन कहीं इमारत गिरी तो कहीं आग ने ली जान; एनसीआरबी चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के शहरों में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुरक्षा को लेकर सरकारी आंकड़े गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। 2020 से 2024 के बीच इमारत गिरने, आग लगने और गड़बड़, मैनहोल या सीवर में गिरने जैसी घटनाओं में 32,596 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 22,291 मौतें आग लगने की घटनाओं में हुईं।

पांच वर्षों में 32,596 मौतें सिर्फ हादसों का आंकड़ा नहीं है। ये शहरों में निर्माण, रखरखाव, सुरक्षा निरीक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हट्टक आधरित आंकड़ों के अनुसार, 2020 में इन घटनाओं में कुल 7,556 मौतें हुईं। 2021 में यह संख्या 6,486,



2022 में 6,529, 2023 में 6,054 और 2024 में 5,971 रही। आग बनी मौतों की सबसे बड़ी वजह : पांच साल के आंकड़ों में आग से 22,291 मौतें हुईं। 2020 में अकेले आग से 5,473 मौतें दर्ज हुईं। 2021 में 4,476, 2022 में

4,237 और 2023 में 3,991 मौतें हुईं। 2024 में यह संख्या फिर बढ़कर 4,114 हो गई। ताजा रिपोर्टिंग के मुताबिक, 2024 में आग से होने वाली मौतों में बड़ी संख्या आवासीय या घरों में लगी आग से जुड़ी थी। 2020 से 2024 के बीच इमारत



कर्मचारियों, रेहड़ी-पटरी वालों व छोटे दुकानदारों को भी हटाय़ा जा रहा है।

4000 से अधिक लोगों को है हटाया जाना : सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं का

अनुमान है कि आइजीआइ एयरपोर्ट से लेकर नई व सेंट्रल जोन तक लगभग 3,500 से 4,000 बेघर लोग व बिखारी रहते हैं। पहले जी- 20 के समय भी ऐसा ही अभियान

चला था, लेकिन आयोजन खम होते ही ये लोग फिर सड़कों पर लौट आए थे।

दीर्घकालीन उपाय नहीं : सामाजिक कार्यकर्ताओं और मामले से जुड़े लोगों का कहना है

सार-समाचार

मुंबई सिटी एफसी ने डिफेंडर लाजार सिकोविच को एक साल के लिए साइन किया



मुंबई । इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) का आगामी सीजन 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले मुंबई सिटी एफसी ने सर्बियाई स्टार लाजार सिकोविच के साथ एक साल का करार किया है। निस (सर्बिया) में जन्मे लाजार ने साल 2010 में सर्बियाई सुपरलीग क्लब 'राड' के साथ अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी। वहां रहते हुए, उन्होंने लोन पर सर्बियाई लीग क्लब 'पार्लिक' के साथ भी अनुभव हासिल किया। साल 2014 में, लाजार सर्बिया के बड़े क्लब 'पार्टिजन' से जुड़े और टोटेंहम हॉटस्पर के खिलाफ यूईएफए यूरोपा लीग मैच में क्लब के लिए अपना आधिकारिक डेब्यू किया। पार्टिजन के साथ अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने दो सर्बियाई सुपरलीग खिताब और एक सर्बियाई कप जीता और फिर स्विट्जरलैंड में 'लुजर्न', इजरायल में 'मकाबी नेतान्या' और हंगरी में 'कासाड' और 'हेनवेड' जैसी टीमों के लिए खेले।

विमेंसएशियाकप

आईसीसी ने पाक बल्लेबाज पर जुर्माना लगाया

दुबई । विमेंस एशिया कप 2026 में हांगकांग, चीन के खिलाफ सोमवार को खेले गए मुकाबले के दौरान आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पाकिस्तानी बल्लेबाज गुल फिरोजा को सजा भुगतनी पड़ी है। उन पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही फिरोजा के खाते में एक डिमिटेड प्लेइंट जोड़ा गया। यह घटना पाकिस्तानी पारी के 5वें ओवर की है, जब फिरोजा को एलबीडब्ल्यू आउट



करार दिया गया। इसके बाद फिरोजा ने अपने बल्ले की ओर इशारा करके फैसले पर असहमति जताई। फिरोजा ने बताया कि गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगी थी। गुल फिरोजा को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अपायर के फैसले पर असहमति जताना शामिल है। यह फिरोजा का 24 महीनों की अवधि में दूसरा अनुशासनात्मक अपराध है।

बैलनडी'ओर 2026

पीएसजी और आर्सेनल समेत ये 5 क्लब 'मैंस क्लब ऑफ द ईयर' के लिए नामित

नई दिल्ली । पेरिस सेंट-जर्मेन, आर्सेनल, बायर्न म्युनिख, नॉर्विजियन क्लब बोडो/ग्लिट्ट स्मेट ब्राजीलियन क्लब फ्लेमिंगो को बैलन डी'ओर 2026 पुरस्कार में 'मैंस क्लब ऑफ द ईयर' अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है। 'पीएसजी' इस अवॉर्ड के मौजूदा विजेता के तौर पर रैस में शामिल है। उन्होंने एक शानदार सीजन में अपना दूसरा चैंपियंस लीग ट्राइटल जीता था। उनका घरेलू और इंटरनेशनल कैपेन भी बहुत सफल रहा, जिसमें लीग 1, फ्रेंच सुपर कप, यूरोपियन सुपर कप और इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते। पेरिस का यह क्लब यूरोप के टॉप क्लबों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद इस सम्मान को बरकरार रखने की उम्मीद करेगा। प्रीमियर लीग ट्राइटल के लिए लंबे इंतजार को खत्म करने के बाद 'आर्सेनल' भी 5 नामित टीम में शामिल है। 'गनर्स' ने 22 साल बाद इंग्लिश चैंपियनशिप जीती और यूरोप में भी आगे बढ़कर एक मजबूत कैपेन पूरा किया। जर्मनी में एक और शानदार सीजन के बाद 'बायर्न म्युनिख' शर्टिलिस्ट में शामिल हुआ है। इस बड़े क्लब ने बूडेसलोगा, जर्मन कप और जर्मन सुपर कप जीते, जिससे घरेलू स्तर पर उनका दबदबा साबित हुआ।

एशियन गेम्स में पारंपरिक नीली जर्सी में खेलेंगे खिलाड़ी

नई दिल्ली। विश्व कप से पहले जर्सी का रंग बदलकर नारंगी करने को लेकर मचे बवाल के बाद अब आगामी एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम में अपनी पारंपरिक नीली जर्सी में नजर आएंगी। मीडिया सूत्रों ने हॉकी इंडिया अग्र्यक्ष दिलीप टिकी के हवाले से लिखा, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने टीम किट के रंगों को लेकर विकल्प दिए थे। इसके बाद हॉकी इंडिया ने भारतीय टीम की जर्सी के लिए नीले रंग को पहली पसंद बनाया। नारंगी रंग दूसरी पसंद है। दिलीप टिकी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों के लिए आयोजित विदाई समारोह से इतर कहा, "मैंने विश्व कप से पहले भी कहा था कि टीम

तिलक ने संभाली पारी, लेकिन 99 पर टूट गया दिल

चेपोक, एजेंसी। दलीप ट्रॉफी 2026-27 के फाइनल में साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा शतक से महज एक रन दूर रह गए। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले के चौथे दिन साउथ जोन की पहली पारी 336 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की विशाल बढ़त मिल गई है। ईस्ट जोन के 708 रन के विशाल स्कोर के जवाब में साउथ जोन पर शुरुआत से ही दबाव था। ऐसे समय में 23 वर्षीय तिलक वर्मा ने एक छोर संभालकर शानदार बल्लेबाजी की। वह लगातार दूसरी सेंचुरी और दलीप ट्रॉफी में अपना तीसरा शतक पूरा करने की कोशिश में थे, लेकिन 99 रन पर उनका सपना टूट गया। साउथ जोन के नौ विकेट गिरने के बाद तिलक पर पारी को संभालने के साथ-साथ स्ट्राइक अपने पास रखने की जिम्मेदारी थी। शतक पूरा करने की कोशिश में उन्होंने ऑफ स्पिनर कुनैन कुरैशी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे गेंदबाज के हाथों में चली गई। इस तरह वह 99 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटे।

मुकेश कुमार रहे ईस्ट जोन के स्टार गेंदबाज
साउथ जोन ने दिन की शुरुआत 242/6 के स्कोर से की थी। तिलक वर्मा और चामा मिलिंद ने शुरुआती दौर में पारी को संभाला। मिलिंद ने 43 रन की अहम पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही साउथ जोन का बल्लेबाजी क्रम बिखर गया।

साउथ जोन ने सिर्फ 18 रन के अंदर अपने चार विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 336 रन पर ऑलआउट हो गई। ईस्ट



जोन के लिए मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3/62 का शानदार स्पेल किया। मोहम्मद शमी, शिखर मोहन और कुनैन कुरैशी ने भी दो-दो विकेट अपने नाम किए।

ईस्ट जोन के पास 372 रन की बड़ी बढ़त
साउथ जोन की पारी खत्म होते ही ईस्ट जोन को पहली पारी में

372 रन की बढ़त हासिल हो गई। अब मुकाबले में सिर्फ एक दिन का खेल बाकी है और ईस्ट जोन ने खिताब जीतने की दिशा में बेहद मजबूत स्थिति बना ली है। ईस्ट जोन की इस बढ़त की नींव कप्तान ईशान किशन की शानदार 270 रन की पारी ने रखी थी। किशन ने अपनी पारी में 30 चौके और 7 छक्के लगाए थे और टीम को 708 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया था।

24 मैचों में औसत 58 से ज्यादा

तिलक वर्मा ने रेड-बॉल क्रिकेट में भी अपनी दावेदारी मजबूत की है। 124 फर्स्ट क्लास मैचों के बाद उनका बल्लेबाजी औसत 58 से ज्यादा है। उन्होंने अब तक 8 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन की 270 रन की पारी दलीप ट्रॉफी फाइनल के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। उनसे आगे सिर्फ रामन लांबा हैं, जिन्होंने 1987 में नॉर्थ जोन के लिए फाइनल में 320 रन बनाए थे।

14 साल बाद खिताब जीतने की ओर

ईस्ट जोन ने 708 रन बनाने के बाद साउथ जोन को 336 रन पर समेट दिया है। इस तरह टीम के पास 372 रन की बढ़त है और मुकाबले में सिर्फ एक दिन बचा है। ऐसे में ईस्ट जोन के पास 14 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीतने का सुनहरा मौका है। दूसरी ओर साउथ जोन को अब मुकाबले में वापसी के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा। तिलक वर्मा का 99 रन पर आउट होना उनकी पारी का सबसे बड़ा अफसोस रहेगा, लेकिन उनकी इस पारी ने एक बार फिर रेड-बॉल क्रिकेट में उनकी बढ़ती साख को साबित किया है।

तिलक का रेड-बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

तिलक वर्मा इस टूर्नामेंट में लगातार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। नॉर्थ जोन के खिलाफ सीमाफाइनल में उन्होंने पहली पारी में नाबद्ध 116 रन बनाकर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला था। उस समय साउथ जोन का स्कोर 80/5 था। इसके बाद दूसरी पारी में भी तिलक ने 181 रन के मुश्किल तथ्य का पीछा करते हुए 79 गेंदों में नाबद्ध 51 रन की पारी खेली थी।

बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा अब होगी भारत से भिड़ंत



नई दिल्ली। महिला एशिया कप 2026 के 12वें मैच में मंगलवार को बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 34 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में गुजरात (10 सितंबर) को उसका सामना भारत से होगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 11 सितंबर को होगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच रविवार (13 सितंबर) को खेला जाएगा।

यूएई 69 पर आउट

यूएई के लिए सुरक्षा कोटे ने 3 विकेट लिए। इंधुजा नंदकुमार ने 2 विकेट लिए अर्चा सुप्रिया और जननी थिरुककुमारन ने 1-1 विकेट लिए। यूएई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 69 रन ही बना पाई। हीना होतचंदानी ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। तीर्थ सतीश ने 11 रन बनाए।

दीप्ति शर्मा छठवें स्थान पर आई, श्री चरणी शीर्ष पर कायम

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा मंगलवार को जारी टी20 गेंदबाजों की सूची में भारत की बाएं हाथ की स्पिनर शीर्ष क्रम पर बरकरार है। वहीं, अनुभवी दीप्ति शर्मा को फायदा हुआ है। ताजा रैंकिंग में श्री चरणी पहले, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन दूसरे, इंग्लैंड की चार्ली डैन तीसरे, दक्षिण अफ्रीका की एन मल्बा चौथे और इंग्लैंड की लॉरेन बेल पांचवें स्थान पर है। भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को दो स्थान का फायदा हुआ है। दीप्ति अब छठे स्थान पर चली गई हैं। दीप्ति मौजूदा एशिया कप में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने तीन मैचों में आठ विकेट लिए हैं और भारतीय टीम को सेमीफाइनल में भारत की बढ़त में अहम भूमिका निभाई है। इंग्लैंड की लिसे स्मिथ एक स्थान के नुकसान के साथ सातवें हैं, और पाकिस्तान की नशारा संधु एक स्थान की नुकसान के साथ आठवें नंबर पर हैं। दक्षिण अफ्रीका की मारिजेन केप को एक स्थान का फायदा हुआ है। वह नौवें नंबर पर हैं। पाकिस्तान की सादिया इकबाल एक स्थान के नुकसान के साथ दसवें स्थान पर हैं। इसके अलावा, एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर रही कुछ अन्य गेंदबाजों को भी आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है।



आयोजन समिति के आवास में ठहरेंगे क्रिकेटर

नई दिल्ली। जापान में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय क्रिकेटर आयोजन समिति की ओर से तय आवास में हो ठहरेंगे। क्रिकेटर्स को विदेशी दौरों पर आमतौर पर मिलने वाले पांच सितारा होटलों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मंगलवार (8 सितंबर)

को यह जानकारी दी। शुक्ला ने कहा कि नागोया में शीर्ष श्रेणी के होटलों की कमी के कारण क्रिकेटरों के ठहरने को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन आवास को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है और बीसीसीआई तथा खिलाड़ी मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। भारतीय दल के विदाई समारोह के दौरान शुक्ला ने कहा, 'आयोजक जो सुविधा दे रहे हैं, हम वहीं

ठहर रहे हैं। हम लगातार यह देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को किस तरह का आवास दिया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। निश्चित तौर पर यह पांच सितारा नहीं है लेकिन अच्छा और आरामदायक आवास है। क्रिकेटर्स के लिए जो आवास तय किये गये हैं, उसकी तस्वीरें और वीडियो हमने मंगाए हैं। मुझे लगता है कि यह आरामदायक है।

महिला एशिया कप: यूएई को हरा सेमीफाइनल में पहुंचा बांग्लादेश

भारत से मुकाबला आज



नई दिल्ली। महिला एशिया कप 2026 के 12वें मैच में मंगलवार (8 सितंबर) को बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 34 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में गुजरात (10 सितंबर) को उसका सामना भारत से होगा। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 11 सितंबर को होगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच रविवार (13 सितंबर) को खेला जाएगा। गुप ए में भारत पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। गुप बी में श्रीलंका पहले और बांग्लादेश दूसरे नंबर पर रहा। यूएई ने टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 103 रन ही बना पाई। शर्मिन अख्तर ने 31 गेंद पर 38 रनों की पारी खेली। कप्तान निगार सुल्ताना ने 28 गेंद पर 23 रन बनाए। जुआरिया फिरदौस ने और नाहिदा अख्तर ने 16-16 रन बनाए।

यूएई 69 पर आउट

यूएई के लिए सुरक्षा कोटे ने 3 विकेट लिए। इंधुजा नंदकुमार ने 2 विकेट लिए अर्चा सुप्रिया और जननी थिरुककुमारन ने 1-1 विकेट लिए। यूएई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 69 रन ही बना पाई। हीना होतचंदानी ने सबसे ज्यादा 18 रन बनाए। तीर्थ सतीश ने 11 रन बनाए।

राबेया खान ने 3 विकेट लिए

मेहुल प्रणव कुलकर्णी ने नाबद्ध 9, समायारा धरनीधरका ने 8, जननी थिरुककुमारन ने 6, रिनिथा रजित्थ ने 5, इंधुजा नंदकुमार ने 3, ईशा ओजा ने 2 और सुरक्षा कोटे ने 1 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए राबेया खान ने 3, नाहिदा अख्तर और मरफूक अख्तर ने 2-2 विकेट लिए। सुल्ताना खातून और फहिमा खातून ने 1-1 विकेट लिए।

एंटी-डोपिंग नियम तोड़ने पर भारतीय कबड्डी खिलाड़ी बृजेंद्र चौधरी पर कार्रवाई

नई दिल्ली। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी (आईटीए) ने सान्या में हुए छठे एशियन बीच गेम्स में ब्रिजोलैमाइड के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद भारतीय कबड्डी खिलाड़ी बृजेंद्र सिंह चौधरी पर एंटी-डोपिंग नियम तोड़ने के लिए कार्रवाई की है। आईटीए ने यह जानकारी मंगलवार को दी। बृजेंद्र चौधरी का यूरेन सैंपल 27 अप्रैल 2026 को एशियन बीच गेम्स के दौरान कॉम्पिटिशन के समय डोपिंग कंट्रोल के लिए लिया गया था। सैंपल में ब्रिजोलैमाइड के लिए 'एडवर्स' एनालिटिकल फाइंडिंग' (नकारात्मक परिणाम) मिली, जो वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) की लिस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ है। ब्रिजोलैमाइड को वाडा की प्रतिबंधित लिस्ट में एक 'स्पेसिफाइड सबस्टेंस' (खास पदार्थ) के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और यह डाइयूरिटिक्स और मारिफिंग एजेंट को एस5 कैटेगरी में आता है। यह प्रतियोगिता के दौरान और उसके बाहर, दोनों समय प्रतिबंधित है।



चौधरी सान्या गेम्स में भारत की 6 सदस्यीय पुरुष कबड्डी टीम का हिस्सा थे। टीम में जितेंद्र यादव, यथार्थ देशवाल, नीरज, जय भगवान और भानु प्रताप तोमर भी शामिल थे। भारत सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 50-

27 से हराकर पुरुषों के फाइनल में पहुंचा था। हालांकि, टीम गोल्ड मेडल के मुकाबले में ईरान को नहीं हरा सकी और 44-31 से हार गई। हाफ-टाइम में भारत 11-23 से पीछे था और दूसरे हाफ में वापसी नहीं कर सका, जिससे ईरान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन बीच गेम्स में पुरुषों की बीच कबड्डी में भारत का यह लगातार दूसरा सिल्वर मेडल था; इससे पहले पिछले एशियन में भी टीम रनर-अप रही थी।

आईटीए ने लागू एंटी-डोपिंग नियमों के अनुसार ओसीए की ओर से यह कार्रवाई की। अब इस मामले को इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन को भेजा जाएगा, ताकि वे अपने नियमों के तहत आगे के नतीजों पर फैसला ले सकें। आईटीए ने कहा कि ओसीए के नजरिए से मामला सुलझा लिया गया है। जिन पक्षों को अपील करने का अधिकार है, वे ओसी के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट' (सीएएस) में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इस बीच, भारत की महिला

कबड्डी टीम ने सान्या में फाइनल में श्रीलंका को 47-31 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इस जीत के साथ ही महिला कबड्डी में लगातार छह एशियन बीच गेम्स का खिताब जीतने का भारत का सिलसिला जारी रहा।

फिर बदला भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग

जर्सी का नारंगी रंग स्थायी नहीं है। इसे भविष्य में बदला भी जा सकता है। अब एशियाई खेलों में नीला रंग वापस आ गया है। टीम नीली जर्सी में खेलेंगी।" हाल ही में नीदरलैंड्स और बेल्जियम में हुए विश्व कप से ठीक पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग पारंपरिक नीले से बदलकर नारंगी किये जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया था जब विपक्ष ने इस पर केंद्र सरकार को निशाना बनाया था। विवाद तब और बढ़ गया था जब दिलीप टिकी ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी या कार्यकारी बोर्ड की जानकारी के बिना जर्सी का रंग बदलने का फैसला लिया गया था। जर्सी का रंग बदलने के पीछे तर्क दिया गया था



कि नीली टर्फ पर नीले रंग की जर्सी में खेलने से दिक्कत आती है। उस समय भी पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा, परमाट सिंह, धनराज पिल्लै, अजित पाल सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस फैसले पर सवाल

एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम जापान खाना

भारतीय महिला हॉकी टीम जापान के आइवी-नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए खाना हो गई। कप्तान सलीमा टेट और कोच शोर्ड मारिन नेतृत्व में भारतीय टीम मंगलवार आठ सितंबर 2026 को बेगलुरु से रवाना हुई। एक आईएच के लॉस एंजिल्स 2028 केवलिफिशियन सिस्टम के तहत, 2026 एशियन गेम्स में महिला हॉकी कॉम्पिटिशन में सबसे ऊपर रहने वाली टीम लॉस एंजिल्स 2028 के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करेगी, बशर्ते उसने पहले किसी दूसरे रास्ते से क्वालिफाई नहीं किया हो। भारतीय टीम का मुख्य लक्ष्य स्वर्ण पदक हासिल

करना और लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करना होगा।

एशियन गेम्स के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम

- गोलकीपर: सविता, बिचू देवी खारीबम।
- डिफेंडर: इशिका चौधरी, सुशीला वानू, पुष्पाममबम, लालथलुआगी, ज्योति, शिल्पी डबास।
- मिडफील्डर: निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनीता टोपा, सलीमा टेट (कप्तान), नेहा, दीपिका सोयंग।
- फोरवर्ड: लालरेमसियामी, रतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, श्रुटी डुंगल।

संक्षिप्त

समाचार

आपदा में मकान, सड़कें और पुल बह गए, भारत-चीन कर रहे मदद; बेली ब्रिज भेजे गए

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पुलों और सड़कों को फिर से बनाने की कोशिश में जुटा है, और भारत और चीन से मदद मांगी है। पड़ोसी देशों ने अस्थायी पुल मुहैया कराने के नेपाल के आग्रह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आपदा में उतरी और मध्य नेपाल में मकान, वाहन, सड़कें और पुल बह गए थे। रसुवा और चितवन के बीच 63 पुल में 41 पुल नष्ट हो गए और चार अन्य आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। काठमांडो पोस्ट की खबर के अनुसार, चीन मुस्तांग में कोरला सीमा चौकी पर दो बेली ब्रिज पहले ही भेज चुका है। भारत ने भी नेपाल को बेली ब्रिज उपलब्ध कराने की पेशकश की है। काठमांडो के एक बौद्ध मठ में बने राहत शिविर में इन दिनों 520 ऐसे बेधर लोगो ने शरण ले रखी है जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। शिविर में एक कोने में बैठे 12 वर्ष के मासूम त्सेरिंग की आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी हैं। उसे भरोसा है कि उसके माता-पिता जल्द लौट आएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। नेपाल में जल प्रलय के बाद अब उत्तर-पश्चिमी हिस्से में मंगलवार रात 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मुस्तांग जिले के लोमान्थांग में था। इससे कोई हताहत नहीं है।

अमेरिका-कनाडा व्यापार युद्ध: ट्रंप के टैरिफ का कनाडा ने दिया जवाब; स्टील समेत क्या सामान महंगे होंगे

टोरंटो, एजेंसी। अमेरिका-कनाडा के बीच ट्रेड वार अब चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के रिश्ते तल्ख होने के बीच कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लागू कर दिया है। कनाडाई सरकार ने कहा कि जवाबी टैरिफ 22 अगस्त से 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले के जवाब में उठाए गए हैं। जवाबी टैरिफ से स्टील, एल्युमीनियम, डेयरी उत्पाद (जैसे पनीर), घरेलू और कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पल्प-पैपर जैसे प्रमुख अमेरिकी उद्योग प्रभावित होंगे। पिछले माह वाशिंगटन में दोनों देशों के बीच महीनो चली व्यापार वार्ता अचानक टूट गई। कनाडा ने आरोप लगाया कि अमेरिकी वातावरण ने अंतिम समय में अनुचित शर्तें थोप दी थीं। ट्रंप ने कनाडा की करंसी और अमेरिका के साथ उसके मुद्रा असंतुलन को अस्वीकार्य करार दिया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और ज्यादा गहरा गया है।

ट्रंप ने पुतिन को मिलाया फोन: यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर हुई बात, यूरोप को लेकर क्या बोले रुसी राष्ट्रपति

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और कहा कि वह यूक्रेन में जारी युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। रुसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन पुतिन ने ट्रंप के इस रुख का समर्थन किया। क्रेमलिन की इस रणनीति को रूस ने कहा गया कि युद्ध समाप्त होने से अमेरिका और रूस के संबंध पूरी तरह सामान्य करने की राह खुलेगी। क्रेमलिन के मुताबिक, पुतिन और ट्रंप के बीच करीब एक घंटे बातचीत हुई। यह बातचीत अमेरिका के विशेष दूत स्टीव वित्कोफ और जेरेड कुशनर की हालिया मास्को और कीव की यात्रा के बाद हुई। दोनों दूत युद्ध खत्म करने के लिए रुकी हुई बातचीत को फिर शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेमलिन के अधिकारी यूरी उशाकोव ने कहा, पुतिन और ट्रंप ने अमेरिकी दूतों की कोशिशों को सकारात्मक माना। पुतिन ने ट्रंप को बताया कि युद्ध खत्म करने में अमेरिका क्या भूमिका निभा सकता है और उन्हें मौजूदा युद्धक्षेत्र की स्थिति की जानकारी भी दी। उशाकोव के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि उनके मौजूदा कार्यकाल में ही युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी सफलता मिले। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होने से दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों को भी बड़ा फायदा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की यूरोप के खिलाफ कोई आक्रामक मंशा नहीं है। क्रेमलिन के अनुसार, पुतिन ने कहा कि रूस से खरबों की बातें यूरोपीय देशों को यूक्रेन का समर्थन बढ़ाने और सैन्य खर्च बढ़ाने का बहाना देती हैं। रूस अपने सैन्य लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यूके छोड़ने पर कानूनी रोक’: विजय माल्या बोले- मैं भगोड़ा नहीं; भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, क्या है मामला

लंदन, एजेंसी। शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर खुद को ‘भगोड़ा’ कहे जाने पर सवाल उठाया है। माल्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं भारत लौटने से भाग नहीं रहा हूं। मुझे भगोड़ा कहने वालों को समझना चाहिए कि मैं 1992 से यूके यानी ब्रिटेन का स्थायी निवासी हूं। फिलहाल कानूनी तौर पर देश छोड़ने पर रोक है। भारत सरकार ने मेरे साथ घोर अन्याय किया। भारत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। अक्टूबर 2025 में जित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया था कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इस सूची में विजय माल्या और नीरव मोदी समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं। यही वजह है कि भारत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, माल्या अब इसी

पहले मोनालिसा, अब रेनॉयर: फ्रांसीसी म्यूजियम से बेशकीमती पेंटिंग चोरी, कब-कब चुराई गई करोड़ों की कलाकृतियां

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस के कैन्सेस-सुर-मेर शहर के मेयर ने मंगलवार को बताया कि चोरों ने फ्रेंच रिवेरा स्थित रेनॉयर म्यूजियम में सेंध लगाकर फ्रांसीसी इमप्रैनिस्ट मास्टर ऑगटे रेनॉयर की चार कीमती कलाकृतियां चुरा लीं। हालांकि, भागते समय चोर दो पेंटिंग म्यूजियम के बगीचे में ही छोड़ गए। म्यूजियम में रेनॉयर की कुल 12 कलाकृतियां थीं। चोरी हुई दो पेंटिंग हैं ‘पोटेंट ऑफ मैडम कोलोना रोमानो’ और ‘यंग वुमन एट द वेल्’ हैं। पुलिस फिलहाल चोरी को अंजाम देने वालों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बीच आए, दुनिया में हुई कला की कुछ दूसरी चर्चित और बड़ी चोरियों पर एक नजर डालते हैं।

इटली के म्यूजियम से रेनॉयर, सेजान और मैटिस की पेंटिंग चोरी : मार्च में चोर उत्तरी इटली के पिाजी शहर के पास स्थित एक निजी म्यूजियम, मैग्नानी रोक्का फ़ाउंडेशन से फ्रांसीसी कला जगत के तीन दिग्गजों की पेंटिंग चुराकर फरार हो गए। चोरी हुई तीन पेंटिंग में ऑगस्टे रेनॉयर की ‘फिश’, पॉल सेजान की ‘रिटल लाइफ़ विद चैरोज़’ और हेनरी मैटिस की ‘ओडालिस्क ऑन द टेरेश’ शामिल थीं। आकार में भले ही ये कलाकृतियां छोटी मानी जाती थीं, लेकिन इनकी कीमत लाखों यूरो आंकी गई थी।

कुछ महीनों बाद बरामद हुई तीनों कलाकृतियां : अगस्त में इटली की कैरांबिनारियो यानी पुलिस बल की आर्ट रिकवरी स्क्वाड ने तीनों पेंटिंग बरामद कर लीं। चोरी के



सिलसिले में संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा माने जा रहे पांच लोगों को हिरासत में लिया गया।

लुव में दिनदहाड़े चोरी, नेपोलियन काल के शाही गहने ले गए चोर : अक्टूबर में दिनदहाड़े हुई एक नाटकीय चोरी में पेरिस के लुव म्यूजियम से फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट और उनके परिवार के शाही गहनों के संग्रह से नौ चीजें चुरा ली गईं। चोरों ने उस समय लुव को निशाना बनाया, जब म्यूजियम आम दर्शकों के लिए खुला हुआ था। उन्होंने म्यूजियम की बाहरी दीवार तक पहुंचने के लिए बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल किया। इसके बाद महज कुछ मिनटों में उन्होंने डिस्प्ले केस तोड़ दिए और करीब 88 मिलियन यूरो (102 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी किए गए सामान में नीलम जड़ा एक डायडेम, एक हार और एक कान की बाली शामिल थी।

ज्यादातर गहने अब भी गायब : चोरी को अंजाम देने वाले चार लोगों के गिरोह को आखिरकार पकड़ लिया गया, लेकिन चोरी किए गए ज्यादातर गहने बरामद नहीं हो सके। केवल

महारानी यूजीनी का होंरे और पन्ने जड़ा ताज ही म्यूजियम के बाहर क्षतिग्रस्त हालत में मिला। माना गया था। इस चोरी के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले म्यूजियमों में शामिल लुव ने अपने निदेशक को बदल दिया और सुरक्षा तथा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया।

मोना लिसा की चोरी ने बड़ाई पेंटिंग की शोहरत : लुव में चोरी और डकैती की कोशिशों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी सबसे मशहूर घटना 1911 में हुई, जब लियोनार्डो दा विंची की ‘मोना लिसा’ अपने फ्रेम से गायब हो गई थी। इसे म्यूजियम के पूर्व कर्मचारी विन्सेन्जो पेरेगिया ने चुराया था। वह म्यूजियम के अंदर छिपा रहा और बाद में अपने कोट के नीचे पेंटिंग छिपाकर बाहर निकल गया।

दो साल बाद फ्नोरेंस में मिली मोना लिसा : चोरी के करीब दो साल बाद ‘मोना लिसा’ को इटली के फ्लोरेंस में बरामद किया गया। इस घटना ने लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे चर्चित और मशहूर कलाकृतियों में शामिल

करने में बड़ी भूमिका निभाई।

बोस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम की चोरी आज भी रहस्य : इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी कला चोरियों में से एक माना जाता है। हालांकि, 35 साल बीत जाने के बाद भी बोस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम से चोरी हुई 13 कलाकृतियों का मामला अब तक अनसुलझा है।

पुलिस अधिकारियों के भेष में म्यूजियम में घुसे थे चोर : 18 मार्च 1990 को सुबह दो लोग बोस्टन पुलिस अधिकारियों के भेष में म्यूजियम में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि वे एक कॉल का जवाब देने आए हैं। म्यूजियम के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने दो सुरक्षा गार्डों को काबू में कर लिया और उन्हें डकट टेप से बांध दिया। इसके बाद करीब 81 मिनट तक उन्होंने म्यूजियम से 13 कलाकृतियां चुरा लीं। चोरी हुई कलाकृतियों में रेम्ब्रांट, वर्मीर, डेगास और मैनेट जैसे महान कलाकारों की बेशकीमती कृतियां शामिल थीं। अधिकारियों का कहना है कि चोरी हुई इन कलाकृतियों की कीमत करीब आधा बिलियन डॉलर तक हो सकती है। हालांकि, म्यूजियम अधिकारियों के मुताबिक इनका असली मूल्य सिर्फ पैसों में नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनकी जगह दूसरी कलाकृतियां नहीं रखी जा सकती। कुछ कलाकृतियों को उनके फ्रेम से काटकर निकाला गया था। इनमें रेम्ब्रांट की मशहूर पेंटिंग ‘स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली’ भी शामिल थी।

बेंजामिन नेतन्याहू का 24 घंटे का यूएन दौरा: ममदानी ने की थी गिरफ्तारी की मांग, फिर क्यों जा रहे न्यूयॉर्क



संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। इसाइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने मंगलवार को बताया कि नेतन्याहू 23 सितंबर की देर रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 24 सितंबर की दोपहर वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उसी रात इसाइल लौट जाएंगे। डैनन ने कहा कि मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री का वहां आना जरूरी है और उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।

ममदानी ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग क्यों की :न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर ममदानी ने नेतन्याहू को ‘युद्ध अपराधी’ बताया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। बाद में उन्हें यह मांग वापस लेनी पड़ी, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का

अमेरिका ने ईरान के पांच तेल टैंकर उड़ाए: जवाब में तेहरान ने जॉर्डन पर दागी मिसाइलें; क्या फिर बढ़ेगा तनाव

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच छह महीने से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। मंगलवार को तनाव फिर बढ़ गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के पांच तेल टैंकरों को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पिछले दो दिनों में अमेरिकी नौसैनिक जहाज को दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की थी।

अमेरिकी युद्धपोत दोनों हमलों से बच गया और गरत जारी रखी। इन हमलों में कोई अमेरिकी सैनिक घायल नहीं हुआ। इसके जवाब में अमेरिका ने पांच टैंकरों को निशाना बनाया। किविक, चार्मिनार, होराइजन-1 और रिको टैंकर गल्फ ऑफ ओमान में थे। पांचवां जहाज डेथॉ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में खरां द्वीप के पास था। अमेरिका ने इन्हीं जहाजों को निशाना बनाया है।

ईरान ने अमेरिका को कैसे दिया जवाब : अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, उसने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागीं। जॉर्डन अमेरिकी सहयोगी है और वहां अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 18 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। दो अन्य मिसाइलें ऐसे इलाकों में गिरीं, जहां कोई आबादी नहीं थी। जॉर्डन ने किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी है। वहीं, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत और बहरीन के पास मौजूद तेल टैंकरों को तुरंत हटने को कहा है। इतना ही



नहीं, ईरान ने दोनों देशों पर अमेरिकी सेना को ठिकाने देने और हमलों में मदद करने का आरोप लगाया। आईआरजीसी ने एक बयान में कहा कि उसने अल-अजराक एयर बेस में अमेरिकी सेना के एफ-35, एफ-16 और एफ-15 लड़ाकू विमानों की मरम्मत, रखरखाव, तैयारी और तैनाती के लिए इस्तेमाल होने वाले एक हैंगर को निशाना बनाया। इसके अलावा, अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए बने एक शेल्टर पर भी हमला किया गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि इस हमले में ‘दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया’।

सिन्धुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जॉर्डन की सेना ने बुधवार को कहा कि उसके वायु रक्षा सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई 20 में से 18 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सेना के अनुसार, बाकी दो मिसाइलें सुनसान इलाकों में गिरी और किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का सबसे बड़ा आर्थिक मोर्चा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बन गया है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता था। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है।

2024 में नेतन्याहू और एक अन्य इसाइली अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत ने कहा था कि नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को लेकर कार्रवाई का आधार है। वारंट में कहा गया कि गाजा में हमला के खिलाफ अभियान के दौरान मानवीय सहायता रोककर ‘भूख को हथियार’ के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

क्या न्यूयॉर्क पहुंचते ही नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं : न्यूयॉर्क शहर के पास आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि ममदानी ने अमेरिकी संघीय सरकार से नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। अमेरिका और इसाइल दोनों आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के कर्मचारियों पर कई प्रतिबंध लगाए

ट्रेड वॉर में ट्रंप की नई चाल: कनाडा के डेयरी-शराब और बाइक अमेरिका में बैन, अब क्या पलटवार करेंगे कार्नी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका कनाडा से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, ज्यादातर शराब और मोटरसाइकिलों पर रोक लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। यह कदम दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच उठाया गया है। यह रोक तीन हफ्ते में लागू होगी। इससे पहले मंगलवार को ही कनाडा ने अमेरिका से होने वाले 20 अरब डॉलर के आयात पर जवाबी टैरिफ लगा दिए थे।

कनाडाई सामानों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स से बाहर रखने का फैसला : मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रोडक्ट्स को अमेरिकी सरकार के बड़े और लंबे समय वाले कॉन्ट्रैक्ट्स से बाहर रखने का फैसला किया। यह कदम कनाडा के जवाबी टैरिफ लागू करने और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के अमेरिका पर देश की निर्भरता कम करने की कोशिशों को तेज करने के वादे के बाद उठाया गया है।

ट्रंप ने त्ख को दिए निर्देश : ट्रंप ने अमेरिकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (त्ख) को निर्देश दिया है कि वह कनाडा के प्रोडक्ट्स को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अपीय घोषित करें। हालांकि, यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कनाडा अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए ‘पूरी और निष्पक्ष बराबरी’ की अनुमति नहीं देता।

‘कनाडा को ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा’ : इससे पहले मंगलवार को कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा की रणनीति अब ज्यादा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने की है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी देश हमें बंधक न बना सके और हम

हैं और इस न्यायालय को खत्म करने की कोशिश की है। इस दौर से जुड़ी सात अहम बातें क्या हैं : दौरा करीब 24 घंटे का होगा: नेतन्याहू 23 सितंबर की देर रात न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और 24 सितंबर की दोपहर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उसी रात इसाइल वापस लौट जाएंगी। ममदानी ने गिरफ्तारी की मांग की थी: न्यूयॉर्क के मेयर ने नेतन्याहू को ‘युद्ध अपराधी’ बताया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। हालांकि शहर के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है। आईसीसी ने नवंबर 2024 में वारंट जारी किया: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसमें गाजा युद्ध के दौरान मानवीय सहायता रोकने और नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप शामिल हैं।



अपनी मर्जी से जी सकें।

यूरोपीय संघ के साथ रिश्ते मजबूत करने की तैयारी : एक कनाडाई अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कनाडा यूरोपियन यूनियन (ध) के साथ ऐसे रिश्ते बनाने पर विचार कर रहा है, जो पूरी सदस्यता तो न हों, लेकिन उसके काफी करीब हों। इन विकल्पों में मौजूदा समझौतों का विस्तार करना, नई संधि पर बातचीत करना या सहयोग के दूसरे रास्ते तलाशना शामिल हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि कनाडा पहले से ही प्रंतों, क्षेत्रों और लेबर ग्रुप्स के सलाह-मशविरा कर रहा है कि थ के साथ किस तरह के गहरे संबंध बनाए जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक किसी एक मॉडल पर फैसला नहीं हुआ है। कार्नी अगले हफ्ते फ्रांस के स्टुसबर्ग जाने वाले हैं। वहां वह 16 सितंबर को यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के ‘स्ट्रेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन’ भाषण में शामिल होंगे।

दशकों पुराने करीबी रिश्ते में बड़ी दूरार : अमेरिका और कनाडा के बीच पैदा हुई यह दूरार दुनिया के सबसे करीबी रिश्तों में से एक को पूरी तरह बदल रही है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और उनके बीच रक्षा एवं सुरक्षा के भी बेहद करीबी संबंध हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नॉर्थ अट्रिकन ट्रेड एग्रीमेंट पर दोबारा बातचीत की थी और बाद में उसकी कई बार लाठी मारी थी, लेकिन अब उनके प्रशासन ने कनाडाई सामानों पर कई टैरिफ लगा दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक की अध्यक्षता में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जन विश्वास अभियान के तहत लंबित सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की।



पाँच साल से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराएं : कमिश्नर

हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जाँच और उपचार में लापरवाही पर होगी कार्यवाही

कमिश्नर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिए निर्देश



रजिस्ट्री में प्रगत संतोषजनक नहीं है। हर गांव में शिविर लगाकर शेष बचे किसानों की फार्मर आईडी कराएं। कमिश्नर ने कहा कि बाढ़ से जन-धन हानि का सर्वे पूरा हो गया है। प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत राशि का तत्काल वितरण कराएं। कलेक्टर टीएल बैठक में भू-अर्जन प्रकरणों की नियमित रूप से समीक्षा करें। भू-अर्जन के प्रकरणों में देरी होने से विकास कार्यों में देरी होती है। भू-अर्जन की प्रक्रिया समय पर पूरी न करके विकास कार्यों में बाधा डालने वालों

विपणन कराएं। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में मिलावटी और अवैध शराब की बिक्री न हो इसे सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक शराब तथा अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करें। अन्य राज्यों से जुड़े क्षेत्रों पर नशीले पदार्थों की बिक्री पर विशेष निगरानी रखें। कोरेक्स तथा अन्य मादक पदार्थों को बेचने वालों के साथ-साथ इनकी सप्लाई करने वालों पर भी कार्रवाई करें। कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि संभाग के सभी जिलों में स्वास्थ्य सूचकांक बेहतर करने की आवश्यकता है। लगातार निर्देशों के बावजूद गर्भवती महिलाओं के पंजीयन और हाईरिस्क महिलाओं के उपचार प्रबंधन में अपेक्षा के अनुसार सुधार नहीं हो रहा है। गर्भवती महिलाओं का समय पर और शत-प्रतिशत पंजीयन कराएं। हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार उपचार देकर पोर्टल पर जानकारी दर्ज करें। रीवा, सीधी और

सिंगरौली जिले में इस संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। कमिश्नर ने कहा कि स्कूलों में जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए शुरू की गई कोचिंग व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें। विद्यार्थियों को लगातार अच्छा कॉरियर मार्गदर्शन मिलने पर उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एक साथ हो जाएगी। यहाँ विद्यार्थियों में अच्छी प्रतिभा है। माहौल बदलेगा तो विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता सुनिश्चित होगी। इन कक्षाओं में टेस्ट सीरीज का भी अभ्यास कराएं। प्रशानिक अधिकारी भी समय निकालकर इनका मार्गदर्शन करें। कमिश्नर ने कहा कि स्वास्थ्य सूचकांकों से जुड़े आंकड़े मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करें। संभाग से लेकर आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर तक दोनों विभाग समन्वय से कार्य करें।

लापरवाह सीएचओ और एएनएम का रुकेगा वेतन

रीवा। स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर करने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। अनमोल पोर्टल पर दर्ज जानकारी के अनुसार 31 अगस्त तक जिले में गर्भवती महिलाओं की दर्ज संख्या 12272 है। इनमें से 9718 महिलाओं का प्रसव सरकारी अस्पतालों में तथा 1544 महिलाओं का प्रसव निजी अस्पतालों में हुआ। इनका प्रतिशत 91 है। इनमें से 873 महिलाओं का प्रसव जिले से बाहर हुआ तथा 137 का प्रसव घर पर ही हुआ। इस संबंध में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधाकर पाण्डेय ने बताया है कि गर्भवती महिलाओं के पंजीयन तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं में 60 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाली सभी एएनएम तथा सीएचओ के वेतन आहरण पर रोक लगाई जा रही है। पोर्टल में निर्धारित बिन्दुओं पर 60 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि होने पर ही वेतन दिया जाएगा। सभी सीएचओ, एएनएम और आशा कार्यकर्ता हर गर्भवती महिला का समय पर पंजीयन और नियमित जाँच कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अपर कलेक्टर ने किया संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण

रीवा। शासकीय संजय गांधी अस्पताल विन्ध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसकी उपचार व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं की मानीटरिंग के लिए कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने राजस्व अधिकारियों की तैनाती की है। उनके द्वारा अस्पताल का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने सुबह 10.30 बजे अस्पताल का निरीक्षण किया। अपर कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधीक्षक डॉ. प्रियंक शर्मा से ड्यूटी चार्ट के अनुसार डॉक्टरों की उपस्थिति, साफ-



सफाई व्यवस्था तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ केवल एक सहायक की अनुमति के संबंध में दिए गए निर्देश के परिपालन की जानकारी ली। अधीक्षक ने बताया कि सभी वार्डों में तैनात सुरक्षार्थी केवल एक व्यक्ति को ही वार्ड में प्रवेश दे रहे हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देशों के अनुसार वार्डों में सफाई के लिए अतिरिक्त सफाईकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। निरीक्षण के समय अन्य डॉक्टरों भी उपस्थित रहे।

टोल फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नम्बर जारी

रीवा। शासन द्वारा बिना पंजीयन के संचालित कारखाने और व्यावसायिक संस्थानों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नम्बर 18002233888 जारी किया गया है। इस संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी श्रीमती संध्या सिंह ने बताया कि कोई भी जागरूक व्यक्ति श्रम प्रहरी के रूप में टोल फ्री नम्बर पर फोन करके अपंजीकृत कारखाने अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थान के संबंध में जानकारी दे सकता है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करना हम सबका सामाजिक दायित्व है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को किया गया रवाना

रीवा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय रीवा के द्वारा आगामी 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया।

प्रचार वाहन के द्वारा रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोक अदालत के आयोजन के संबंध में प्रचार प्रसार किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती शिवानी शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्रा, जिला रजिस्टार श्री पन्ना नागेश, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा, लीगलएड डिफेंस कार्डिसल के श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री आनंद पाण्डेय, श्री मंजूर अहमद, श्रीमती आरती तिवारी

एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि आगामी 12 सितम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक वॉरंट, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्रोलिएटिओन प्रकरण इत्यादि के प्रकरण निराकरण के लिए रखे जायेंगे।

भूमि आवंटन के संबंध में आपत्ति 17 सितम्बर तक

रीवा। नायब तहसीलदार हुजूर नगर यतशी शुक्ला ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय निर्माण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय भूमि आवंटन का आवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए कलेक्टर न्यायालय में ग्राम बोदा की शासकीय भूमि नम्बर 1225/1 रकबा 0.02 हेक्टेयर एवं भूमि क्रमांक 1228/1 रकबा 0.125 हेक्टेयर के आवंटन के लिए आवेदन किया गया है।

रोजगार मेला कन्या महाविद्यालय में 16 सितंबर को

रीवा। युवा संगम कार्यक्रम के तहत शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में 16 सितंबर को वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा। रोजगार मेले में रीवा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। रोजगार मेले में 20 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुवे ने बताया कि रोजगार मेले में आने वाले युवाओं के पंजीयन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। मेले में शामिल

होने वाले युवाओं के लिए आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए युवाओं की आयु 18 से 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए, समस्त ट्रेडों से आईटीआई उतीर्ण तथा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त युवा रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। वेतन एवं भत्ते 12 हजार रुपए से 25 हजार रुपए कंपनीवाइज अलग-अलग निर्धारित किया गया है। रोजगार मेले में आने वाले युवाओं को अपने

साथ समग्र आईडी, मूल अंकसूची की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लाना अनिवार्य होगा। उप संचालक रोजगार अनिल दुवे ने बताया कि रोजगार मेले में वेलेस्पन कॉपी लि. अंजर गुजरात, वर्धमान यार्न्स सतलपुर मण्डीदीप भोपाल, एमआरएफ टायर्स दाहेज गुजरात, प्रगतिशील बायोटेक प्रा. लि. रीवा, यूनो मिंडा ईवी सिस्टम गुरुग्राम हरियाणा, एचडीएफसी

लाइफ इंश्योरेंस रीवा, देवभाल रीवा, प्रगतिशील एग्रोटेक प्रा. लि. रीवा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर, बैंक आफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लि. बैंगलोर, आईटीसी लिमिटेड, प्रभा बायोफ्लान्ट्स प्रा. लि. रीवा, ट्राइडेंट कंपनी बुधनी गुजरात, एक्सस्टोपिएस बेलेनेस प्रा. लि. रीवा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड म.प्र., वेयर हाउस, सीआईआई माडल कॉरियर सेंटर, फोक्सकॉन कंपनी बैंगलोर तथा प्रतिभा सिंटेक्स प्रा. लि. पौधमपुर इंदौर की कंपनियां शामिल हो रही हैं।

नवीन भवन से विकास की नई यात्रा प्रारंभ होगी : सांसद

हनुमना को मिली विकास की नई सौगात, आठ करोड़ की लागत से नवनिर्मित तहसील भवन का हुआ लोकार्पण

मऊगंज। हनुमना तहसील में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में सांसद श्री जनार्दन मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता



विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल ने की। नवीन भवन में तहसील से संबंधित विभिन्न कार्यालयों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन को एक ही स्थान पर बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्य अतिथि सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने कहा कि

आठ करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह भवन क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मऊगंज में लगभग पचास करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के भवनों का निर्माण भी प्रगत पर है।

मच्छर से फैलने वाले रोग डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से बचें

रोग के लक्षण दिखने पर कराएं निःशुल्क जाँच

रीवा। जिला मलेरिया अधिकारी ने आम जनों को मच्छर से फैलने वाले रोग मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने की सलाह दी है। जिला मलेरिया अधिकारी ने कहा कि मच्छरों से बचाव व नियंत्रण के लिए जनभागीदारी व जनजागृति का होना आवश्यक है। वर्षाकाल में जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाने से उनमें मच्छरों की उत्पत्ति व वृद्धि होती है। ये मच्छर रोगी व्यक्ति को काटने पर संक्रमित हो जाते हैं व इन संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, रोग का प्रसार होता है।

मलेरिया बुखार से ग्रस्त रोगियों को ठंड लगकर बुखार आना, सिरदर्द, भूख न लगना सामान्य लक्षण है। डेंगू से अधिक तेज बुखार, शरीर पर लाल चकते, माशपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, आंखें घुमाने में दर्द सामान्य लक्षण हैं। गंभीर स्थिति में मुँह, नाक और आंखों से खून आना, पेट दर्द, उल्टी होना और आंखों में खून उतरना, प्लेटलेट्स में अत्यधिक गिरावट होना जैसे लक्षण होते हैं। चिकनगुनिया बुखार में उंगलियों और हाथ-पैर के जोड़ों में तेज दर्द, सिर दर्द, हल्का बुखार बना रहना, त्वचा में चकते होना सामान्य लक्षण है। जिला

मलेरिया अधिकारी ने बताया कि डेंगू व चिकनगुनिया बुखार टाईगर अथवा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन में सक्रिय रहता है। बीमारी फैलाने वाले मच्छर घरों में नमी वाले अंधेरे स्थान में विश्राम करते हैं और साफ व रुके पानी में पनपते हैं। यह मच्छर हमारे घरों में व आसपास पानी से भरे बर्तनों, गमले, टंकी, टायर, मटके, कूलर, टूटा-फूटा कबाड़ में भरे पानी, नल, हेण्डपंप व कुएं के आसपास भरे पानी में अपने अण्डे देते हैं और 7 से 8 दिन में अंडे से मच्छर बनने का जीवनचक्र पूर्ण हो जाता है।

रीवा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस

वन विभाग, संरक्षण संगठनों और हितधारकों ने गिद्ध संरक्षण के लिए तैयार किया रोडमैप

रीवा। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस के अवसर पर गत दिवस जयंती कुंज वन कार्यालय में विशेष बैठक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डीएफओ लोकेश निरापूरे की उपस्थिति में रीवा जिले में गिद्ध संरक्षण के लिए भविष्य की कार्ययोजना और रोडमैप तैयार करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों, गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य कर रहे स्थानीय संगठनों, समुदाय के प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों ने सहभागिता की। बैठक में गिद्धों के घोंसलों एवं प्रजनन स्थलों की



सुरक्षा, नियमित मॉनिटरिंग, आवासीय क्षेत्र के संरक्षण, आवास क्षति को रोकने, सुरक्षित भोजन एवं मृत पशुओं के शवों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गिद्धों के लिए हानिकारक दवाओं के उपयोग एवं नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर

पहचान एवं निगरानी, प्रजनन गतिविधियों का अध्ययन, आवास संरक्षण, समुदाय एवं हितधारकों के बीच जागरूकता, सुरक्षित भोजन की उपलब्धता तथा गिद्धों के लिए हानिकारक पशु चिकित्सा दवाओं के प्रति जागरूकता जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इन संरक्षण प्रयासों में वन विभाग का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। बैठक में रीवा के गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र में गिद्धों के लिए गिद्ध फीडिंग स्टेशन स्थापित करने की आगामी योजना पर भी चर्चा की गई, जिससे गिद्धों को सुरक्षित एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ एवं जलवायु कार्यकर्ता देवादित्य सिन्हा

ने गिद्ध संरक्षण, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम में एसडीओ फॉरेस्ट, रेंजर, डिप्टी रेंजर तथा सेमरिया, सिरमौर और रीवा क्षेत्र के वनरक्षक भी शामिल हुए। वनकर्मियों ने अपने मैदानी अनुभव साझा किए। वहीं डीएफओ ने गिद्ध संरक्षण को लेकर वन विभाग के अनुभव, प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस के संदेश को युवाओं तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी बायपास क्षेत्र में किशोरों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।